04 - भारत-जापान की साझेदारी बदलेगी शक्ति समीकरण

05 - प्लास्टिक वस्तुओं से छुटकारा पाने की दरकार

A Daily News Magazine
भोपाल
शुक्रवार, 03 जुलाई, 2026

06 - रूपाखेड़ा, नाहरखेड़ा, तिलगारा के किसान उच्च...

07 - 10 हजार स्मार्ट क्लास शुरू करने की तैयारी

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 23, अंक 301, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

क्या अमेरिका-ईरान संघर्ष में बड़ी हार अरब देशों की हुई है?

मनाल खलील

अमेरिका और ईरान के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर साइन होने से मिडिल ईस्ट में मिलिट्री टेंशन कुछ समय के लिए कम हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी शुरुआती स्टेज में है और इसके आखिरी नतीजों के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाज़ी होगी।

फिर भी, एक ज़रूरी सवाल सामने आ रहा है, और वह यह है कि इस पूरे झगड़े में सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होगा? फ़ारस की खाड़ी के अरब देशों को ये आशंका है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत से तेहरान को 'बहुत ज़्यादा छूट' मिल सकती है, जिससे इस इलाक़े में ईरान का रसूख और बढ़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच साइन किए गए मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर किसी साफ़ रोक का ज़िक्र नहीं है।

यह एक ऐसी बात है जिसने खाड़ी देशों के लिए और चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि ये वही मिसाइलें हैं जो हाल के झगड़े के दौरान खाड़ी देशों पर दागी गई थीं। इनसे जान-माल का बहुत नुक़सान हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ईरान की मिसाइल क्षमता को ख़त्म करने को अपने मुख्य लक्ष्यों में से एक बताती रही।

हालांकि, पेरिस दौरे के दौरान ट्रंप ने अपने रुख़ में थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा कि 'अगर दूसरे देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तो ईरान को उनमें से कुछ से दूर रखना ग़लत होगा।' किंग्स कॉलेज लंदन में सिक्योरिटी स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर एंड्रियास क्रेग के मुताबिक़, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अभी भी अरब देशों के लिए एक गंभीर सिक्योरिटी चुनौती बना हुआ है। ईरान के मिसाइल स्टॉक को पूरी तरह ख़त्म करने की मांग एक कामयाब समझौते में रुकावट बन सकती है।

एंड्रियास क्रेग के मुताबिक खाड़ी देशों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना होगा, मिसाइल डिफ़ेंस सिस्टम का विस्तार करना होगा और इंटरसेप्टर मिसाइलें बनानी होंगी। इसके अलावा क्रेग के मुताबिक खाड़ी देशों को 'भविष्य में सीधे टकराव से बचने के लिए तेहरान के साथ संपर्क बनाए रखना शामिल है।'

इस बात के बावजूद कि इस युद्ध के दौरान खाड़ी के अरब देशों को काफ़ी नुक़सान हुआ और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरियां भी सामने आईं, एंड्रियास क्रेग के मुताबिक़, 'स्ट्रेटेजिक नज़रिए से, इसराइल सबसे बड़ा हारने वाला देश लगता है। उसने अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमैटिक और मिलिट्री कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के साथ ख़र्च किया है। इस सोच को मज़बूत किया है कि वह अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के तहत अमेरिका को इस इलाक़े में महंगे तनाव की ओर धकेल रहा है। इसके उलट, खाड़ी के देश धीरे-धीरे 'अमेरिका फ़र्स्ट' पॉलिसी की मांगों को मान रहे हैं। ये देश एनर्जी सप्लाई पक्का करने से लेकर रीज़नल संकटों में बीच-बचाव करने की भूमिका निभाने तक, कई तरह से अमेरिका के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण डिप्लोमैटिक और स्ट्रेटेजिक फ़ायदा है। दूसरी तरफ़, वॉशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में रिसर्चर और लेक्चरर हसन मुनीमना के अनुसार, खाड़ी के देश इस संकट से फ़ायदा उठाने वालों में से हो सकते हैं,क्योंकि लंबे युद्ध की स्थिति में उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। हाल के सालों में, खाड़ी के देशों ने अपनी इकॉनमी में विविधता लाने के लिए बड़े प्लान शुरू किए हैं, जिसके तहत टूरिज़्म और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है।

अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में ईरान के रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 300 बिलियन डॉलर का एक बड़ा फंड बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। उम्मीद है कि खाड़ी देश इस फंड के लिए मुख्य फाइनेंशियल रिसोर्स देंगे। दूसरी ओर, ईरान पहले ही इस इलाक़े के उन देशों से मुआवज़े की मांग कर चुका है, जिन्होंने उसके खिलाफ हमलों में हिस्सा लिया या मिलिट्री बेस के रूप में मदद दी। कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों ने भी मांग की है कि ईरान अपने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से हुए नुकसान की भरपाई करे।

इस तरह, एक मुश्किल स्थिति बन रही है जिसमें खाड़ी देशों को न केवल युद्ध की कीमत चुकानी पड़ सकती है, बल्कि शांति की भी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अभी तक, खाड़ी देशों को हुए कुल नुकसान के बारे में कोई ऑफिशियल डेटा जारी नहीं किया गया है। दूसरी ओर, एंड्रियास क्रेग का कहना है कि खाड़ी देश ईरान को कभी भी 'साफ़ छूट' नहीं देंगे और कोई भी रिकंस्ट्रक्शन पैकेज सिर्फ़ अप्रत्यक्ष रूप से, शर्तों के साथ और कमर्शियल आधार पर ही लागू किया जाएगा। साथ ही, आर्थिक एक-दूसरे पर निर्भरता इन देशों को ईरान के व्यवहार पर असर डालने का एक नया ज़रिया भी दे सकती है।

कुछ विश्लेषकों के अनुसार ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने वाले कारकों में होर्मुज़ स्ट्रेट का विशेष महत्व है। ईरान इस महत्वपूर्ण जलमार्ग का उपयोग बातचीत के दौरान दबाव के प्रभावी स्रोत के रूप में करता रहा है। यह स्थिति खाड़ी देशों के लिए चिंता का कारण है क्योंकि उनका प्रमुख तेल और गैस निर्यात इसी मार्ग पर निर्भर करता है। क्रेग के मुताबिक़, होर्मुज़ स्ट्रेट किसी भी संभावित समझौते का सबसे संवेदनशील और जटिल बिंदु रहेगा।

पिछले हफ़्ते, ईरान और ओमान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि वे होर्मुज़ स्ट्रेट में शिपिंग के फ़्यूचर मैनेजमेंट और पॉसिबल टोल पर एक एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मस्कट ने घोषणा की कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइज़ेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में एक टेम्परारी कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि जहाज़ होर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित तरीके से गुज़र सकें। इस कदम का मकसद अंतरराष्ट्रीय क़ानून और समुद्र के क़ानून के तहत बिना फ़ीस के नेविगेशन की स्वतंत्रता पक्का करना है। हालांकि, यह मुद्दा हाल के दिनों में फिर से तनाव की वजह बन गया है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच समझ बनी रहती है, तो इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों को फिर से बनाने, यहाँ तक कि कुछ हद तक नॉर्मल करने का रास्ता बन सकता है।

एंड्रियास क्रेग के अनुसार, इन देशों के पास अभी मिलिट्री बेस, बड़े फाइनेंशियल रिसोर्स, एक मॉडर्न लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में असर और असरदार डिप्लोमैटिक रिलेशन हैं, लेकिन जो कमी लगती है वह है आपसी तालमेल। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, क़तर, कुवैत और बहरीन सभी में अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, और इन बेस को मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सुरक्षा ढांचे की नींव माना जाता है।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

चंदा गिनने वाले आरोपियों के घर पर चलेगा बुलडोजर

● राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े ऐक्शन की तैयारी ● जांच के लिए एक बार फिर राम मंदिर पहुंची यूपी पुलिस ● चंपत राय पर एफआईआर के लिए वकीलों का प्रदर्शन

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब ट्रस्ट के सदस्यों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा- पूरी गलती गोपाल राव की है। वे राजनीति कर रहे हैं। वो सबको उलझा देते हैं। वो राम की परंपरा नहीं मानते। गोपाल राव राम मंदिर के निर्माण प्रभारी और ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य थे। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। इस बीच, सुबह 11.45 बजे अयोध्या में 500 से ज्यादा वकील सड़क पर उतर आए। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एफआईआर की मांग कर नारेबाजी की। सिविल लाइन चौकी

जाकर उन तीनों समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दी। उधर, अयोध्या पुलिस सुबह करीब 11 बजे राम मंदिर पहुंची। दो घंटे तक जांच की।

ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से पूछताछ संभव- पुलिस ने अयोध्या जेल में 30 जून को आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ की थी, अब आगे जांच कर रही है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से रविवार को 3 घंटे पूछताछ हो चुकी है। अब उसे क्रॉस चेक करने के लिए अनिल मिश्रा से आज पूछताछ हो सकती है। आरोपियों लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा की नियुक्ति में उनके रोल की पड़ताल करेगी। चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था।

भारत आ रहे जहाज को लूटने की कोशिश नाकाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत आ रहे एक जहाज को लूटने की कोशिश को भारतीय नौसेना ने नाकाम कर दिया है। ये जहाज अब पूरी तरह से सुरक्षित है। जहाज पर कल रात समुद्री लुटेरों का हमला हुआ था। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल ने समुद्री डकैती की एक कोशिश को नाकाम किया है। बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो जहाज (एमवी गोल्डन आर्सेनल) पर चढ़े। इस जहाज पर ही लुटेरों का हमला हुआ था। जहाज पर एक भारतीय क्रू मेंबर भी मौजूद था। यह जहाज भारत के लिए जरूरी सामान लेकर जा रहा था। जहाज के क्रू ने खुद को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर लिया और कम्युनिकेशन चैनल के जरिए डकैती की कोशिश की जानकारी दी। युद्धपोत जहाज की तरफ बढ़ा तो लुटेरे भाग गए।

दतिया विधानसभा उपचुनाव-30 जुलाई को वोटिंग, 3 अगस्त को नतीजे

6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी, राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म होने से खाली थी सीट

भोपाल (नप्र)। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई, नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई तथा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके बाद 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया 4 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी।

आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू

निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार अब दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मतदान सभी केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से कराया जाएगा।

विजयवर्गीय बोले- बीजेपी ही जीतेगी

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- दतिया उपचुनाव में निश्चित रूप से भाजपा ही जीतेगी। इस सवाल पर कि क्या बीजेपी के उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा ही होंगे, विजयवर्गीय बोले- ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। जो उम्मीदवार आएगा, आपको बताया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशंकित अल्प वर्षा की स्थिति से निपटने पूर्व तैयारियों की समीक्षा कर दिये निर्देश

आशंकित अल्प वर्षा से निपटने के लिए सभी विभाग करें समन्वित तैयारी : मुख्यमंत्री

पूर्व चेतावनी के लिए बनाए जाएंगे राज्य स्तरीय जल डैशबोर्ड

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संभावित अल्प वर्षा की स्थिति को चुनौती नहीं, बल्कि बेहतर योजना, वैज्ञानिक खेती और समयबद्ध तैयारी के अवसर के रूप में लिया जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसानों को समय पर आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं, जिससे प्रदेश में कृषि उत्पादन और किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में इस वर्ष प्रदेश में संभावित अल्प वर्षा की स्थिति के मद्देनज़र किसान कल्याण एवं कृषि विकास, जल संसाधन, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित अन्य संबंधित विभागों की अब तक की पूर्व तैयारियों की गहन समीक्षा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश का प्रत्येक किसान मौसम की चुनौतियों का सामना वैज्ञानिक सोच और उचित तैयारी के साथ करे। समय पर सही निर्णय और विभागों के प्रभावी समन्वय से हम संभावित अल्प वर्षा के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को कम पानी और कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों की खेती के लिए व्यापक स्तर पर जागरूक किया जाए। उन्होंने ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर तथा कोदो-कुटकी जैसी मोटे अनाज एवं दलहनी फसलों को अपनाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि ये फसलें कम पानी में भी बेहतर उत्पादन देने के साथ किसानों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को जल्दबाजी में बुआई नहीं करने के लिए भी प्रेरित किया जाए। खेतों में पर्याप्त नमी आने के बाद ही बुआई की जाए तथा नमी संरक्षण के उपाय अपनाए जाएं। साथ ही कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कृषि वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों के सुझावों को प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुंचाया जाए, जिससे वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त फसल का चयन कर सकें। इसके लिए कृषि विस्तार तंत्र को और अधिक सक्रिय बनाया जाए।

अगले दो वर्षों की तैयारी

प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में वैकल्पिक स्रोतों का चिन्हांकन एवं टैंकर व्यवस्था की आकस्मिक योजना तैयार कर अमृत 2.0 के अंतर्गत जल प्रदाय योजनाओं का समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की ग्रामवार समीक्षा, बंद/अपूर्ण नल-जल योजनाओं की मरम्मत का 90 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा। 'जलाभिषेक 2.0' अंतर्गत प्रदेश में पुराने तालाबों, बावड़ियों, कुओं एवं अन्य जल संरचनाओं का सर्वे एवं जीर्णोद्धार, वीबीपी रामजी अभिसरण से प्रति विकासखंड न्यूनतम 100 जल संरचनाओं का पुनर्जीवन 2 वर्षों में किया जायेगा। भूजल पुनर्भरण अभियान के तहत सभी विकासखंडों में रिचार्ज शाफ्ट, चेक डैम, स्टॉप डैम एवं खेत-तालाब निर्माण का मिशन मोड कार्यक्रम; 'खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में' सिद्धांत पर चलाया जाएगा। नहरों की सफाई मरम्मत रबी से पूर्व पूर्ण, टेल-एंड तक पानी पहुंचाने की जवाबदेही तय की जायेगी।

सुप्रभात

तुम्हारे मौन
को बार-बार पढ़ने की
कोशिश करता हूँ
तुम्हारे मौन में
अनगिनत भाव हैं
अनगिनत बिंब हैं
अनगिनत शैलियां
प्रतीत होती हैं
ऐसा लगता है
तुम्हारे मौन में
सादियों के पारंपरिक
शब्दों के गहरे अर्थ हैं
जिन्हें खोज-खोज
मैं थक चुका हूँ
पक चुका हूँ
उम्र के इस
आधे पड़ाव पर,
पर आज तक
न समझ सका
तुम्हारे मौन को
कभी-कभी
बुद्ध-सा प्रतीत होता है
तुम्हारा मौन...
जिसे जानने के लिये
समझने के लिये
हर बार
मैं विफल हूँ
मैं चार अक्षर
पढ़कर भी अनपढ़ हूँ
शब्दों से अधिक
ताकतवर होते हैं
मौन के अनंत
गहरे भावार्थ
तुम्हारे मौन की संधियाँ
मेरे 'मौन' से
कब संगम करेंगी?
कब मेरे मन में।

- सुरेश सौरभ

बंधुआ मजदूरों के लिए 'बीएसएफ' बन रही फरिश्ता

● पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से लगते गांवों में परिजनों से करवा रही मुलाकात

नई दिल्ली (एजेंसी)। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से लगते गांवों में 'बंधुआ मजदूरी' करने वाले भोले-भाले और दिमागी रूप से थोड़े कमजोर लोगों के लिए यहां तैनात बीएसएफ की 100वीं बटालियन फरिश्ता बन रही है। इस बटालियन ने दूसरे राज्यों से भटककर आने इस तरह के पांच मजदूरों को उनके परिजनों से मिलवाने का काम किया है। जो दूसरे राज्यों से भटककर यहां आ पहुंचे थे। फिर इन्हें रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से उठाकर सीमावर्ती गांवों में ले जाया गया। जहां इनसे दिन-रात बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा था।

बीएसएफ का साथ, ऐसे बिकाश अपने परिजनों तक पहुंचे- तभी बीएसएफ के एक अधिकारी की नजर इनके ऊपर पड़ी। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने उड़ीसा का नाम ना बताते हुए केवल अपने गांव का नाम बताया। फिर उस गांव की सर्च करने पर पता लगा कि वह गांव उड़ीसा के बालासोर जिले में है। वहां बीएसएफ की टीम के एक हवलदार को भेजकर घर वालों से बिकाश के बारे में सारी जानकारी ली गई। मामला पता लग गया कि यह दिसंबर 2025 से अपने घर से किसी तरह से लापता हो गए थे। इसके बाद इनके परिजनों को अमृतसर बुलाया गया। जहां बीएसएफ ने बिकाश को उनके सुपुर्द किया। सूत्रों का कहना है कि पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से

लगते गांव मुल्लाकोट, मोदे, धनुआ खुर्द, रानियो, पिंडोरी और बच्ची भिंड समेत कई गांवों में इस तरह से रास्ता भटके करीब 150 लोगों के बंधुआ मजदूरी करने का शक है। सूत्रों का कहना है कि इस बात को सोचते हुए दो दिन पहले ही बीएसएफ अधिकारियों ने बॉर्डर से लगते गांवों के किसान और डेयरी चलाने वालों की मीटिंग कर कहा है कि अगर उनके घर में इस तरह से कोई बंधुआ मजदूरी कर रहा है तो उसे बीएसएफ या लोकल पुलिस के हवाले कर दिया जाए। बाद में पता लगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीएसएफ जांच में यह भी पता लगा है कि ऐसे कुछ लोगों को रात के वक्त जंजीरों में भी जकड़ कर रखा जा रहा है।

● **बंधुआ मजदूरों को मुक्त करा रही बीएसएफ-** इसी तरह के एक ताजा मामले में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ की 100वीं बटालियन के कमांडेंट अजय तिवारी के नेतृत्व में बीएसएफ की टीम ने बेहद सराहनीय कार्य करते हुए उड़ीसा के रहने वाले एक शख्स को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया। जो सात महीने पहले किसी तरह से अपने घर से भटक कर यहां आ पहुंचा था। इनसे यहां खेत और पशुओं को चारा खिलाने और भैसों का दूध निकलवाने का काम कराया जा रहा था। वह भी बिना किसी मेहनताना दिए हुए। सूत्रों ने बताया कि बीएसएफ की इस 100वीं बटालियन को इसकी भनक करीब 15 दिन पहले उस वक्त लगी। जब मजदूरी से मुक्त कराए गए उड़ीसा के बालासोर में एक गांव के रहने वाले बिकाश देवरी एक खेत में डरे-सहमे से काम कर रहे थे।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20°c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 03 जुलाई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

नगा-कुकी में फिर टकराव जबरदस्त तनाव में मणिपुर

समूहों के बीच फिर झड़प, उपद्रवियों ने 20 घरों को किया आग के हवाले

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर के कामजोंग जिले में बुधवार को फिर से हिंसा भड़क गई। भारत-म्यांमार सीमा के पास के गांवों में नगा और कुकी गुटों के बीच हुई सशस्त्र झड़पों में 20 से ज्यादा घर जला दिए गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, हिंसा की शुरुआत सुबह हुई जब कुकी गांव के हथियारों से लैस लोगों ने नगा गांव पर हमला किया

और कम से कम 10 घरों में आग लगा दी। दोपहर में स्थिति और बिगड़ गई जब संदिग्ध उग्रवादियों और हथियारों से लैस गांव के स्वयंसेवकों ने इलाके के अन्य गांवों पर जवाबी हमले किए। बाद में हुई हिंसा में नगा समुदाय के कम से कम 12 और घर जला दिए गए। प्रभावित गांवों में सुरक्षा बलों को भेजा गया और हालात सामान्य करने के लिए इलाके में कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन कड़ी नजर रखी जा रही है। हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।

पटना के बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा

30 जुलाई को डाले जाएंगे वोट

पटना (एजेंसी)। निर्वाचन आयोग ने पटना की बेहद वीआईपी मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस सीट पर आगामी 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। यह सीट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बांकीपुर सीट को भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए इस उपचुनाव पर न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष की भी पैनी नजरें टिकी हुई हैं। चुनाव की तारीखें सामने आते ही पटना में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पटना की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह चुनाव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफे के कारण हो रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार, उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होकर 13 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी (जांच) होगी, जबकि प्रत्याशी 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।

बेंगलुरु में पत्थर खदान में चट्टान गिरी, 8 की मौत

सभी मजदूर बिहार के रहने वाले, 18 लोग काम कर रहे थे

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक के बेंगलुरु में गुरुवार सुबह पत्थर खदान पर हुए हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। घटना के दौरान 18 मजदूर का काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक, साउथ तालुक इलाके में मौजूद कावेरी क्रशर कंपनी की

खदान में खनन चल रहा था। इसी दौरान 40 फीट ऊंचाई से चट्टान का बड़ा टुकड़ा मजदूरों पर गिरा। घटना में कई मजदूर घायल भी हुए हैं। सभी का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। एक्सकेवेटर चला रहे परशुराम ने बताया कि काम शुरू करने के लिए जैसे ही मैं मौके पर पहुंचे और मशीन चालू की, तभी पहाड़ी का एक हिस्सा ढह गया। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन उस समय नीचे करीब 18 लोग काम कर रहे थे। हादसा इतना अचानक हुआ कि मजदूरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मलबे में दबे 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया।

पीएम मोदी ने पीएम सनाए को बताया अपनी छोटी बहन

● कहा-विश्व पटल पर भारत-जापान गढ़ेंगे नए आयाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की पीएम सनाए तकाइची ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत-जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लिया। इसके बाद साझा प्रेस वार्ता में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों की साझेदारी को और सुदृढ़ करने का संकल्प दिया। प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री तकाइची को अपनी छोटी बहन कह कर संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी हैं। प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए, आज एआई के क्षेत्र में हमने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है।

प्रधानमंत्री ने किया जी-7 समिट का जिक्र- पीएम मोदी ने आगे कहा कि सनाए तकाइची नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो साझा बौद्ध विरासत का केंद्र है। जी-7 में मैंने कहा था कि उथल पुथल के माहौल में यह एक वैश्विक स्ट्रेटजिक एसेट है। भारत-जापान की साझेदारी इस कसौटी पर खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक में जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती निभाई है।

● डिफेंस, एआई से लेकर क्रिटिकल मिनरल्स पर बात- दोनों नेताओं के बीच निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, सप्लाई चेन, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय-वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में ताकाइची का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की साथी ताकाइची को अपनी छोटी बहन बताया। उन्होंने कहा कि योर एक्सीलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री तकाइची। इंडिया-जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री तकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।

विभाजन के बाद भारत आने वाले लोग शरणार्थी नहीं

● भागवत ने विस्थापितों के संघर्ष को सराहा, कहा-वह योद्धा थे ● बोले-धर्म के प्रति प्रेम के कारण कठिनाइयों और दर्द को झेला ● विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कभी हार नहीं मानी

नागपुर (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि 1947 के विभाजन के बाद भारत आने वाले लोग शरणार्थी नहीं थे, बल्कि संघर्ष के योद्धा थे जिन्होंने मातृभूमि और धर्म के प्रति प्रेम के कारण कठिनाइयों और दर्द को झेला। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पाकिस्तान में अपनी संपत्ति और व्यवसाय छोड़कर भारत आने का निर्णय लिया। भागवत नागपुर में सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के 75वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस सोसाइटी का संचालन सिंधी समाज की ओर से किया जाता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि विभाजन के बाद इन लोगों ने जानबूझकर भारत आने का निर्णय लिया, क्योंकि वे उस भूमि में रहना चाहते थे जहां वे बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सकें। उन्होंने कहा-वे शरणार्थी नहीं थे, हालांकि वे विस्थापित थे। वे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम के चलते कष्ट झेला। उन्होंने करियर या धन नहीं, बल्कि देश और धर्म को चुना। जीवन की कठिनाइयों पर उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी को हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि फिर से उठने का प्रयास करना चाहिए। अंततः सफल भी वही होता है। उन्होंने सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की 75 वर्षों की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे पड़ाव किसी संस्था के किए गए कामों की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं।

पद्मश्री अवार्डी पूर्व छात्र की तस्वीर देखकर जब नैक टीम के सदस्य कह उठे- वॉव... एलुमिनाई स्टार परफॉर्मर !

नरसिंहपुर से डा. बृजेश शर्मा

करीब 3 साल पहले जब स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर में नैक पियर टीम निरीक्षण करने पहुंची थी तो प्राचार्य कक्ष में लगी एक फोटो देखकर वह गदगद हो गई। अनायास उनकी प्रतिक्रिया थी- वॉव ! एलुमिनाई स्टार परफॉर्मर ! कॉलेज से निकले स्टूडेंट की यह थी।

प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आर.बी. सिंह ने यह वाकया सुनाया। 10 अक्टूबर 2023 को नैक मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु की नैक पियर टीम यहां पीजी कॉलेज पहुंची थी। उस वक्त टीम के चेयरपर्सन डॉ. बसंत सिंह, पूर्व कुलपति डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट डेक्कन पुणे, डॉ. केपी सोमा सद्भि सीनियर स्टेशन वेस्टर्न डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, प्राध्यापक डॉ. मल्लानागौड़ा आर पाटिल पूर्व प्राचार्य प्रोग्रेस एजुकेशन सोसायटी शिवा प्रोग्रेसी कॉलेज ऑफ कामर्स एजुकेशन कम्प्यूटर एण्ड मैनेजमेंट गोवा, तीन सदस्यीय नैक टीम में शामिल रहे। दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन 10 अक्टूबर को महाविद्यालय कार्यालयीन स्थिति तथा कम्प्यूटर विभाग का अवलोकन किया। इसी क्रम में नैक टीम ने एनएसएस, एनसीसी, संस्कृत विभाग, भूगोल विभाग, मनोविज्ञान विभाग, क्रीड़ा विभाग, आईक्यूएसी, लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

इस मौके पर प्राचार्य डॉ ममता शर्मा एवं आईक्यूएसी समन्वयक डॉ. सतीश दुबे, समन्वयक सदस्य डॉ आर.बी. सिंह, डॉ मनीष अग्रवाल, डॉ नरेश कुमार सोनी, डॉ. तफज्जुल खान तथा अब्दुल कलीम खान आदि मौजूद रहे। नैक पियर टीम के निरीक्षण के दौरान प्राचार्य, समन्वयक और सभी प्रोफेसर के माथे पर कुछ शिकन थी। यह तनाव उस समय काफूर हो गया जब टीम प्राचार्य कक्ष में बैठी। उन्होंने अपने सामने दीवार पर लगी एक फोटो देखी।

इस दौरान एक सदस्य सोफे से उठकर फोटो के नजदीक पहुंचे और पूछा- यह फोटो ? प्राचार्य डॉ. ममता शर्मा ने बताया कि यह कॉलेज के छात्र रहे विजय दत्त श्रीधर हैं। उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील पद्मश्री अवार्ड दे रही हैं। यह सुनते ही अन्य दो सदस्य भी फोटो के नजदीक पहुंच गए। फोटो देखकर गदगद हुए। एक सदस्य के मुंह से निकला- " वॉव एलुमिनाई स्टार परफॉर्मर।

इससे प्राचार्य कक्ष का माहौल खुशनुमा हो गया। जिन प्राचार्य, प्रोफेसर और समन्वयक के चेहरे पर तनाव झलक रहा था, उन सभी के चेहरे पर सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद झलकने लगी।

वाकया सुनाने वाले वर्तमान प्राचार्य डॉ. आर.बी. सिंह उस समय कालेज की समन्वय समिति के सदस्य थे। पद्मश्री से विभूषित विजयदत्त श्रीधर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से डी. लिट.की मानद उपाधि लेने के एक सप्ताह बाद 27 जून 2026 को नरसिंहपुर प्रवास के दौरान पीजी कॉलेज पहुंचे थे। यहां नरसिंहपुर के प्रबुद्ध नागरिकों ने उनके सम्मान में विचार विमर्श और अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया था।

दतिया में बेटे की हैवानियत

हत्या के बाद कंकाल होने तक पिता की लाश को छिपाया, 6 महीने तक बोलता रहा झूठ

दतिया (नप्र)। जिले से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 24 साल के कलयुगी बेटे ने महज 40 हजार रुपये के विवाद में अपने सगे पिता की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। सनसनीखेज बात यह है कि आरोपी ने हत्या के बाद पुलिस और समाज से बचने के लिए पिता के शव को करीब छह महीने तक अपने ही घर के भीतर एक लोहे के बड़े बक्से में बंद करके रखा।

जब शव पूरी तरह गल गया और केवल कंकाल बचा, तब आरोपी ने अपने सगे चाचा की मदद से उन अवशेषों को पास की एक नदी में फेंक दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी नितिन बुंदेला और उसके चाचा कल्ला उर्फ एस्पेंद्र बुंदेला को गिरफ्तार कर लिया है।

ट्रैक्टर की किस्त के पैसों को जुए-शराब में उड़ाए

इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कांड की शुरुआत तब हुई जब 45 वर्षीय उदयभान सिंह बुंदेला ने अपने बेटे नितिन को खेती के खर्च और ट्रैक्टर की किस्त चुकाने के लिए 40,000 रुपये दिए थे।

पिताजी मुंबई गए हैं... 6 महीने तक बोलता रहा झूठ

वारदात को अंजाम देने के बाद नितिन ने गांव वालों और रिश्तेदारों के बीच यह अफवाह फैला दी कि उसके पिता काम के सिलसिले में मुंबई गए हैं। महीनों तक जब उदयभान वापस नहीं लौटे, तो शक के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। दतिया पुलिस ने जब कड़ाई से मिसिंग पर्सन की जांच शुरू की, तो कड़ियों से कड़ियां जुड़ती गईं और नितिन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने नदी से अवशेष बरामद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

छिंदवाड़ा सांसद बंटी साहू लापता हैं !

कमलनाथ के बाद अब भाजपा सांसद के लगे पोस्टर, समस्याओं से परेशान लोग बैनर लेकर सड़कों पर उतरे

छिंदवाड़ा (नप्र)। जिले की राजनीति में इन दिनों 'लापता' पोस्टरों का दौर चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विधानसभा क्षेत्र जैतपुर में उनके लापता होने के पोस्टर लगाए गए थे, वहीं अब सांसद विवेक बंटी साहू को लेकर भी ऐसा ही विरोध सामने आया है। गुरुवार को ग्राम घोघरा में ग्रामीणों ने सांसद के 'लापता' होने के पोस्टर हाथों में लेकर प्रदर्शन किया और एक वीडियो जारी करते हुए क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि वे लंबे समय से बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

ग्रामीणों ने वीडियो में कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद गांवों की तस्वीर नहीं बदली है। जब भी किसानों और आम लोगों पर संकट आया, तब सांसद जनता के बीच दिखाई देने के बजाय धार्मिक यात्राओं में व्यस्त रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धार्मिक आस्था और यात्रा का वे पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जनता द्वारा चुने गए सांसद का पहला दायित्व क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना और लोगों के बीच उपस्थित रहना है।

ग्रामीणों ने प्रतीकात्मक रूप से सांसद को 'लापता' बताते हुए कहा कि वे अपने जनप्रतिनिधि को तलाश रहे हैं ताकि उन्हें गांव की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके। उनका कहना था कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि गांव-गांव पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जनता को अपनी समस्याएं बताने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है।

खाद संकट से किसान परेशान, समय पर नहीं हो पा रहे कृषि कार्य- ग्रामीणों ने सबसे बड़ी समस्या खरीफ सीजन में खाद की कमी को बताया। उनका कहना है कि यूरिया और डीएपी खाद की भारी किल्लत बनी हुई है। किसान कई दिनों से समितियों और बिक्री केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो रही। समय पर खाद नहीं मिलने से फसलों की बुवाई और शुरुआती देखभाल प्रभावित हो रही है, जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं हुई तो पूरी खेती प्रभावित हो सकती है।

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आज भी स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। कई मोहल्लों में लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता है, जबकि बारिश के मौसम में भी पेयजल की समस्या जस की तस बनी हुई है।

● अब नार्थ ईस्ट में भारत को घेरने की तैयारी, बढ़ेगी टेंशन

चीन का बांग्लादेश और म्यांमार में सीपीईसी जैसा प्लान

बीजिंग (एजेंसी)। भारत के पूर्वी बॉर्डर के आसपास पकड़ बनाने के लिए चीन एक अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अरबों डॉलर के चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) की तरह बीजिंग का प्लान अब म्यांमार के रास्ते चीन को बांग्लादेश से जोड़ने वाला गलियारा बनाने का है। दक्षिण एशिया में अपने महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी प्लान के तहत चीन अरब सागर तक पहुंच बनाने के बाद बंगाल की खाड़ी तक जाने वाले रास्ते पर नजर जमाए हुए है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने ट्रांसनेशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रस्ताव बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान की हालिया बीजिंग यात्रा के दौरान उनके सामने रखा है।

● बांग्लादेश देगा चीन का साथ!- चीन के प्रस्ताव को ढाका की हरी झंडी मिली है। बांग्लादेशी अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित कॉरिडोर से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ढाका के बंदरगाहों का आधुनिकीकरण होगा और चीनी बाजारों तक पहुंच बेहतर करने में मदद मिलेगी। भारत बॉर्डर के पास पाकिस्तान में बीजिंग का सीपीईसी है, जो पश्चिमी चीन को बलूचिस्तान से जोड़ता है। इसी तरह का कुछ रूट अब वह भारत के पूर्वी बॉर्डर पर चाहता है। सीपीईसी पर भारत विरोध जताता रहा है क्योंकि यह कॉरिडोर गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। इस इलाके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। प्रस्तावित चीन-म्यांमार-बांग्लादेश कॉरिडोर को म्यांमार से होकर गुजरेगा। इससे नई दिल्ली के लिए यह प्रस्ताव ध्यान देने लायक है।

● चीनी कॉरिडोर में मौका देख रहा ढाका- ढाका में चीनी कॉरिडोर को एक आर्थिक पहल के तौर पर पेश किया जा रहा है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने बताया है कि प्रस्तावित रास्ता चीन के युन्नान प्रांत के कुनमिंग से शुरू होगा, म्यांमार के मांडले से गुजरेगा और फिर यांगून और क्यूकफ्यू की ओर बढ़ेगा। आखिर में सड़क और रेल मार्गों के जरिए बांग्लादेश के चटगांव और कॉक्स बाजार से जुड़ेगा। बांग्लादेशी मीडिया और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह प्रस्तावित कॉरिडोर जमीन पर उतरता है तो सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चीनी निवेश को बढ़ावा देगा। बांग्लादेश की चीनी और दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों तक पहुंच बेहतर होगी, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में उछाल आएगी।

ममता से अलग हुआ बागी गुट बोला-हम असली टीएमसी

चुनाव आयोग से मुलाकात की, कहा-जल्द से जल्द फैसला लें

नई दिल्ली/कोलकाता (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने गुरुवार दोपहर चुनाव आयोग से मुलाकात की। बागी गुट का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिला। विधायकों ने पार्टी में हुए संगठनात्मक बदलावों और नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मान्यता देने की मांग की। मुलाकात के बाद बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने कहा- हम ही असली टीएमसी हैं, चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी। उम्मीद है वे जल्द फैसला लेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 22 जून को कोलकाता में प्रतिनिधि बैठक हुई थी। इसमें नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद 3 जून को टीएमसी के 80 में से 58 विधायक ममता बनर्जी के नेतृत्व से अलग हो गए थे। इसके अलावा 15 जून को टीएमसी के 20 सांसदों ने भी पार्टी छोड़कर त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी में विलय कर लिया था।

बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसी बगावत- 20 जून 2022 को महाराष्ट्र में शिवसेना के 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए। तब उद्धव सीएम थे। राज्यपाल ने उन्हें फ्लोर टेस्ट को कहा। उद्धव सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट नहीं रोका तो उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। 30 जून 2022 को शिंदे भाजपा के समर्थन से सीएम बन गए। फिर दोनों गुट एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने फैसला स्पीकर राहुल नार्वेकर पर छोड़ दिया।

सतना में गर्ल्स स्कूल में गिरा पेड़, 2 युवतियां दबीं

भोपाल में बारिश, दमोह में बाढ़ जैसे हालात, 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में गुरुवार को भोपाल समेत 8 जिलों में तेज बारिश हुई। आंधी-बारिश के बीच सतना में महारानी लक्ष्मी बाई गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा पेड़ गिर गया। 2 युवतियां मलबे में दब गईं। एक बाइक और बाउंड्री के किनारे लगा स्ट्रीट फूड का ठेला भी पेड़ और मलबे की चपेट में आ गया।

मानसून ने गुरुवार को पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया। पांढुर्णा, सीहोर, रतलाम, ग्वालियर, रीवा और दमोह में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। दमोह में नदी-नाले ऊफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रदेश में मानसून की एंट्री 24 जून को हुई थी। इस तरह मानसून ने 9 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया। हालांकि, इस बार मानसून निर्धारित समय से करीब 9 दिन देरी से पहुंचा। सामान्य तौर पर यह 15 जून तक प्रदेश में दस्तक दे देता है।

6 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट- आज हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों में इन जिलों में 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। वहीं अशोकनगर, देवास, खंडवा, बैतूल, सागर, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

तेज बहाव में बह गए दो बाइक सवार, एक लापता

इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के अहीरखेड़ी-काकड़ इलाके में रपटा पार करते समय दो बाइक सवार तेज बहाव में बह गए। दोनों की उम्र 20 से 22 वर्ष बताई जा रही है। इनमें मनीष को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि महेश तेज बहाव में लापता हो गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर उसकी तलाश में जुटी हुई है।

भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा, शाजापुर, बैतूल, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में गुरुवार को आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है।

इंदौर में जलभराव, नाले में गिरी थार

बुधवार को इंदौर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। वार्ड क्रमांक-80 में बारिश का पानी दुकानों में घुस गया, जबकि कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। इसी दौरान एक थार वाहन नाले में गिर गया। वाहन में पूरा परिवार सवार था। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मदद कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है।

सेवा, समर्पण, नवाचार और सांस्कृतिक गौरव के साथ धूमधाम से मनाया गया भारतीय स्टेट बैंक का 71वाँ स्थापना दिवस

भोपाल। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक का 71वाँ स्थापना दिवस स्थानीय प्रधान कार्यालय, भोपाल में अत्यंत उत्साह, गरिमा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। दिनभर आयोजित कार्यक्रमों में सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व, तकनीकी नवाचार, कर्मचारी सम्मान एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने पूरे आयोजन को यादगार बना दिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ बैंक डे प्रतिज्ञा के साथ हुआ, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने बैंक के मूल्यों, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके पश्चात स्थानीय प्रधान कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक श्री प्रभाष कुमार सुबुद्धि ने अत्याधुनिक डिजिटल स्क्रीन एवं फायर हाइड्रेंट सिस्टम का उद्घाटन कर बैंक की आधुनिक एवं सुरक्षित कार्यसंस्कृति को नई दिशा प्रदान की।

इसके उपरांत आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने रक्तदान कर मानव सेवा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता का परिचय दिया। वहीं रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति तथा भारतीय स्टेट बैंक की गौरवशाली परंपरा को आकर्षक रंगों के माध्यम से जीवंत रूप प्रदान किया।

सायंकाल प्रशासन अकादमी में आयोजित भव्य सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं गणेश वंदना से हुआ। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक भोपाल सर्किल की गत एक वर्ष की उपलब्धियों एवं विकास यात्रा पर आधारित प्रेरणादायी वीडियो का प्रदर्शन किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉ. नारायण व्यास, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सेवानिवृत्त अधीक्षण पुरातत्वविद् एवं भारतीय संस्कृति, इतिहास तथा पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए विख्यात विद्वान तथा सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी एवं पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री पवन जैन का मुख्य महाप्रबंधक श्री प्रभाष कुमार सुबुद्धि द्वारा शॉल एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर आत्मीय सम्मान किया गया।

इस अवसर पर Growing Up with SBI गतिविधि के विजेताओं एवं बैंक के उत्कृष्ट खिलाड़ी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक ने अपने स्वागत उद्बोधन में बैंक की गौरवशाली 71 वर्षीय यात्रा, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, तकनीकी नवाचार, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कर्मचारियों के समर्पण को भारतीय स्टेट बैंक की सबसे बड़ी शक्ति बताया।

कार्यक्रम के दौरान पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री पवन जैन ने अपने प्रभावशाली काव्य पाठ से उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया। इसके पश्चात एसबीआई लेडीज़ क्लब द्वारा गीत एवं नाटिका की मनमोहक प्रस्तुति तथा सुप्रसिद्ध ध्रुपद संगीत की प्रस्तुति ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत की गरिमा को जीवंत कर दिया। बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत गीत, कविता, नृत्य एवं नाट्य प्रस्तुतियों ने पूरे सभागार को तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान कर दिया।

समारोह में महाप्रबंधक (नेटवर्क-2) श्री नीलांक रॉय, महाप्रबंधक (नेटवर्क-3) श्री मनोज कुमार, बैंक के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी, लेडीज़ क्लब की सदस्याएँ, अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवारजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक केवल देश का सबसे बड़ा बैंक ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण, वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग, सामाजिक सरोकार एवं उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अग्रणी संस्थान है। स्थापना दिवस पर आयोजित सेवा, सम्मान, नवाचार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बैंक की सेवा, समर्पण और उत्कृष्टता की कार्य संस्कृति को नई ऊँचाइयाँ प्रदान की हैं।

उल्लास, उत्साह, संगठनात्मक एकता और सांस्कृतिक गरिमा से परिपूर्ण इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि भारतीय स्टेट बैंक अपने गौरवशाली 71 वर्षों की विरासत को संजोते हुए भविष्य में भी ग्राहक सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और अधिक सशक्त रूप से आगे बढ़ाता रहेगा।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्कूल रेडीनेस मेला आयोजित

भोपाल। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से संचालित समर कैम्प 2026 कार्यक्रम के अंतर्गत भोपाल जिले की समस्त 73 सेक्टरों एवं 1,800 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित स्कूल रेडीनेस मेला -2 का सफल समापन हुआ। मेले में 5-6 वर्ष आयु के बच्चों का पाँच विकास क्षेत्रों भाषा, संख्या ज्ञान, संज्ञानात्मक क्षमता, शारीरिक विकास तथा सामाजिक-भावनात्मक कौशल में पुनः आकलन किया गया। 26 मई को आयोजित पहले मेले की तुलना में उनकी प्रगति को व्यक्तिगत रिपोर्ट कार्ड में दर्ज कर अभिभावकों को सौंपा गया। जिले भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक माह तक चले माता सहभागिता कार्यक्रम के बाद बच्चों में स्पष्ट सुधार देखे जाने की जानकारी दी, जिसके दौरान माताओं को 'एक खेल, एक कहानी, एक कविता' थीम पर प्रतिदिन वीडियो भेजकर घर पर सरल गतिविधियाँ कराने हेतु मार्गदर्शन दिया गया था। भोपाल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शाहीन, आरती, इंद्रा, सरिता व पेचिदा ने कहा, कि आज जो देखने को मिला वह उल्लेखनीय था। जो बच्चे एक माह पहले रंग या अंक तक ठीक से पहचान नहीं पाते थे, वे आज आत्मविश्वास के साथ गतिविधियाँ पूरी कर रहे थे।

मेले के दौरान चयनित केंद्रों का भ्रमण करने वाले अधिकारी सीडीपीओ मृदुल मालवीय ने बताया कि कार्यक्रम में माताओं, सामुदायिक स्वयंसेवकों तथा स्थानीय विद्यालय प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता रही। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा, यही वह सामुदायिक स्वामित्व है, जिसकी हमें अपेक्षा थी। माताएँ अब केवल जानकारी प्राप्त करने वाली नहीं रहीं वे अपने बच्चों की शिक्षिका के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में नर्मदा समग्र की समीक्षा बैठक की।

सहकारी सप्ताह के अंतर्गत राज्य स्तरीय सहकारी प्रदर्शनी का शुभारंभ

सहकारिता आंदोलन को जन-जन तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम बनेगी प्रदर्शनी : मंत्री सारंग

भोपाल (नप्र)। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की स्थापना के पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारी सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी प्रदर्शनी का शुभारंभ गुरुवार को सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मंत्री श्री सारंग ने फीता काटकर प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया तथा विभिन्न सहकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय सहकारी संगठनों, शासकीय विभागों, महिला स्व-सहायता समूहों एवं उत्पादक संगठनों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शित उत्पादों, नवाचारों एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर प्रतिनिधियों से संवाद किया तथा सहकारिता आधारित आर्थिक गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर बल दिया।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश में विकास, जनकल्याण और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए निरंतर नए-नए प्रकल्पों पर कार्य कर रहे हैं। सहकारिता इस विकास यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश में पृथक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया तथा देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। आज सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 29 जून से 5 जुलाई तक पूरे मध्यप्रदेश में 'सहकारी सप्ताह' का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारिता की अवधारणा को जन-जन तक पहुँचाया जा रहा है। राज्य स्तरीय सहकारी प्रदर्शनी भी इसी श्रृंखला का महत्वपूर्ण आयोजन है।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि यह प्रदर्शनी सहकारिता से जुड़े सभी प्रमुख आयामों की व्यापक झलक प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों, उपलब्धियों, नवाचारों और योजनाओं का प्रभावी प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएँ नवाचार के माध्यम से जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार कर रही हैं, उनका प्रदर्शन भी इस प्रदर्शनी में किया जा रहा है। इससे सहकारी संस्थाओं को नए बाजार उपलब्ध होंगे, उत्पादों का प्रचार-प्रसार होगा तथा प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूती मिलेगी।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता प्रधानमंत्री श्री मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को साकार करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। किसानों, महिलाओं, युवाओं, कारीगरों एवं ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकारिता के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सहकारी संस्थाओं से नवाचार, गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जनसहभागिता को प्राथमिकता देते हुए अपने उत्पादों एवं सेवाओं को अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ सहकारी संस्थाओं को विपणन का प्रभावी मंच उपलब्ध कराने के साथ उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करती हैं तथा नई पीढ़ी को सहकारिता आंदोलन से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनती हैं।

मंत्री श्री सारंग ने हस्तशिल्प कारीगरों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन स्वरूप सिलाई मशीन सहित विभिन्न टूल किट एवं आवश्यक सामग्री का वितरण किया। साथ ही मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

तीन दिवसीय प्रदर्शनी में प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों, महिला स्व-सहायता समूहों तथा उत्पादक संगठनों द्वारा कृषि, दुग्ध, बीज, उर्वरक, मत्स्य, वनोपज, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, महिला सशक्तिकरण, हस्तशिल्प, उद्यमिता विकास, एफपीओ, सौर ऊर्जा तथा ग्रामीण आजीविका से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन (सांची), मार्कफेड, इफको, कृभको, नेफेड, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक), जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), नाबार्ड सहित अनेक प्रमुख सहकारी संस्थाओं ने अपने स्टॉल स्थापित किए हैं।

कार्यक्रम में प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ श्री अभिजीत अग्रवाल, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता, प्रबंध संचालक श्री महेंद्र दीक्षित, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक संघ सहित विभिन्न विभागों एवं सहकारी संस्थाओं के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्याएँ, कृषक, उद्यमी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

सुधीर श्रीवास्तव ने संभाला पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर का कार्यभार

देश के इस अग्रणी ट्रेनिंग सेन्टर में इंजीनियर्स और नॉन-इंजीनियर्स को मिलती है आधुनिक ट्रेनिंग

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निदेशक (वाणिज्य एवं तकनीकी) श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने कंपनी के प्रतिष्ठित ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर (पीडीटीसी) के निदेशक का कार्यभार आज संभाल लिया है।

गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का यह ट्रेनिंग सेंटर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे सेंट्रल इंडिया (मध्य भारत) का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र है। इस ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में विद्युत वितरण क्षेत्र से जुड़े इंजीनियर्स को उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ गैर-तकनीकी श्रेणी के कार्मिकों को भी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निदेशक (वाणिज्य एवं तकनीकी) श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने कार्यभार ग्रहण करने के दौरान कहा कि इस अग्रणी ट्रेनिंग सेंटर की साख के अनुरूप प्रशिक्षण की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा, ताकि बिजली क्षेत्र की आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा सके। इस अवसर पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग सहित वरिष्ठ अधिकारियों और ट्रेनिंग सेंटर के स्टाफ ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा का उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने किया अभिनंदन

भोपाल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा का उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने गुरुवार को निवास कार्यालय, भोपाल में आत्मीय अभिनंदन किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. साहा और उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल के मध्य विभिन्न समसामयिक विषयों और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती स्वप्ना साहा भी उपस्थित थीं। त्रिपुरा मुख्यमंत्री डॉ. साहा मध्यप्रदेश प्रवास पर हैं। मुख्यमंत्री डॉ. साहा भोपाल में आयोजित 28वें एओएमएसआई मिड-टर्म कन्वेंशन एवं 14वें एओएमएसआई पोस्टग्रेजुएट कन्वेंशन-मिडकॉम्स 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया, मध्यप्रदेश स्टेट चैप्टर तथा पीपुल्स यूनिवर्सिटी, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में यह राष्ट्रीय सम्मेलन 2 से 4 जुलाई 2026 तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन की थीम क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन अर्थात् समग्र सर्जन का निर्माण है। यह सम्मेलन ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के क्षेत्र का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अकादमिक आयोजन है, जिसमें देश-विदेश के प्रख्यात विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षक, शोधकर्ता तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थी सहभागिता करेंगे। सम्मेलन में नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान, आधुनिक तकनीकों, जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं तथा चिकित्सा शिक्षा के विविध आयामों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

एमपी ट्रांसको ने श्यामपुर में ऊर्जीकृत किया 50 एमवीए क्षमता का अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर

भोपाल (नप्र)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने सीहोर जिले की पारेषण व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करते हुए 132 केवी सब स्टेशन श्यामपुर की क्षमता वृद्धि की है। जहाँ 50 एमवीए क्षमता का एक अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर स्थापित कर उसे ऊर्जीकृत किया गया है। इस ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकृत होने से सब स्टेशन की क्षमता बढ़कर 140 एमवीए की हो गई है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस सब स्टेशन में यह तीसरा पावर ट्रांसफार्मर स्थापित कर ऊर्जीकृत किया गया है। इससे सब स्टेशन में बढ़ते लोड का उचित प्रबंधन किया जा सकेगा।

राजा रघुवंशी मर्डर केस

मेघालय सरकार सोनम की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची, विपिन ने कहा- कल होगी सुनवाई

इंदौर (नप्र)। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब मेघालय सरकार सोनम की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मेघालय सरकार सोनम की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इस मामले में कल सुनवाई भी हो सकती है।

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की उसकी ही पत्नी सोनम रघुवंशी ने शिलॉन्ग हनीमून पर लेकर जाकर साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। इस मामले में शिलॉन्ग पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि सोनम सहित कुछ आरोपी जमानत पर बाहर हैं, जबकि कुछ अभी भी जेल में हैं। सोनम को जमानत मिलने के बाद से राजा रघुवंशी के परिवार में रोष व्याप्त था। वे चाहते हैं कि राजा की हत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पिछले दिनों सोनम की जमानत रद्द करने के लिए पुलिस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से सोनम की जमानत रद्द नहीं हो सकी थी। इसके बाद अब मेघालय सरकार ने सोनम की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

ब्लिंकिट बॉय बनकर आए बदमाशों ने 40 लाख लूटे

रतलाम में जान से मारने की धमकी दी, शराब कलेक्शन की रकम से भरा बैग छीनकर भागे

रतलाम (नप्र)। रतलाम के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के कर्मचारियों से 40 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया गया। वारदात 29 जून की दोपहर करीब 3 बजे शहर सराय इलाके में हुई। बदमाश ब्लिंकिट कंपनी के डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनकर आए थे और स्कूटी से फरार हो गए।

कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने लूट और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित कारोबारी मनीष पटवा ने पुलिस को बताया कि उनके दोस्त गौरव शर्मा के रतलाम में शराब के ठेके हैं।

26 से 28 जून तक बैंक बंद रहने के कारण 25 से 28 जून की शराब बिक्री का करीब 40 लाख रुपए का कलेक्शन सुरक्षित रखने के लिए उनके पास भेजा गया था।

ऊपर घर ले जाते समय बैग छीनकर भागा बदमाश

गौरव के कर्मचारी अमित ने यह रकम मनीष के कर्मचारी फरदीन और उसके पिता फिरोज को दी। नकदी गिनने के बाद मनीष ने दोनों से कहा कि रकम काले बैग में रखकर ऊपर घर में ले जाएं। इसी दौरान ब्लिंकिट की ड्रेस पहने और चेहरे पर कपड़ा बांधे एक बदमाश वहां पहुंचा। उसने फरदीन को जान से मारने की धमकी दी और बैग छीनकर बाहर खड़ी स्कूटी पर बैठे अपने साथी के साथ गायत्री टॉकीज की ओर भाग निकला। फरदीन और फिरोज ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे फरार हो गए। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।

दोस्त के उज्जैन से लौटने के बाद दर्ज कराई रिपोर्ट

घटना के समय गौरव शर्मा उज्जैन में थे। उनके रतलाम लौटने के बाद मनीष पटवा ने स्टेशन रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी जितेंद्र जादौन ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

हवाला कारोबारी है पीड़ित, पुलिस को लग गई थी भनक

सूत्रों के अनुसार, पीड़ित कारोबारी मनीष पटवा का नाम हवाला कारोबार से भी जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह भी जानकारी सामने आई है कि लूट की सूचना पुलिस को घटना वाले दिन ही मिल गई थी, लेकिन उस समय कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी।

संपादकीय

सतही सद्भावना की चिट्ठी !

भारत और पाकिस्तान की 117 हस्तियों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर टकराव का रास्ता छोड़कर बातचीत शुरू करने की जो पैरवी की है, वो सतही सद्भाव का इजहार ज्यादा है। क्योंकि इस पूरे मामले में असल जवाबदेह पाकिस्तान है, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और न ही ऐसा होने की गारंटी है। ऐसे में एकतरफा दोस्ती का हाथ बढ़ाने का कोई व्यावहारिक मतलब नहीं है। इस चिट्ठी पर भारत के 61 और पाकिस्तान की 56 हस्तियों के हस्ताक्षर हैं। जिनमें कई पूर्व अधिकारी, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। भारत की ओर से जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 61 लोगों और पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 लोगों ने चिट्ठी पर साइन किए हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि दोनों देश टकराव के बजाए बातचीत का रास्ता चुनें ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। इनका कहना है कि लगातार बढ़ती शत्रुता से दोनों देशों के विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और आम नागरिकों के हित प्रभावित हो रहे हैं।

खास बात यह है कि यह पहल ऐसे समय में की गई है जब हाल के महीनों में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव बना हुआ है। दूसरे, बीच में भारत पाक के बीच ट्रैक 2 बातचीत की बात भी चली थी, जिसे भारत ने आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया। इसके पहले संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने भी दोनों देशों के बीच बातचीत की पैरवी की थी। इससे यह संदेश गया कि दोनों देशों के बीच रिश्तों की ठंडी बर्फ पिघलाने की कोई कोशिश चल रही है। लेकिन यहां असल सवाल व्यावहारिकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में पाक से रिश्ते सुधारने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, खुद बिना बुलाए लाहौर तक पहुंच गए। लेकिन नतीजा क्या निकला, हमे जवाब में पठानकोट, पुलवामा और पहलगाम जैसे पाक प्रायोजित हत्याकांड मिले। जाहिर है कि पाक में सरकार पर असल नियंत्रण सेना का है, जो अपना वजूद भारत विरोध में ही सुरक्षित मानती है। आज की तारीख में असली सराकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तो मुखौटा पीएम हैं। मुनीर कट्टर भारत विरोधी हैं और भारत को खत्म करना या उसे लगातार दर्द देते रहने की नीति है। दूसरे, कश्मीर मामले में पाक जमीनी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, भले ही उसके कब्जाए गुलाम कश्मीर में लोग अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर पर दावा किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में भारत किसी से बात भी करे तो किससे करे? दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव कम होने की भी संभावना नहीं है। 25 फरवरी 2021 को दोनों देशों ने एलओसी पर 2003 के सीजफायर समझौते का फिर से पालन करने पर सहमति जताई। इसके बावजूद हालिया आतंकी घटनाओं के बाद सीमाओं पर तनाव बना हुआ है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच पूर्णकालिक कूटनीतिक रिश्ते भी नहीं हैं। व्यापार और संचार भी बंद है। पाक अभी भी लगातार आतंकी संगठनों को पनाह और सभी तरह की मदद दिए जा रहा है। भारत-पाक शीर्ष नेताओं के लिखी चिट्ठी पर जम्मू-कश्मीर भाजपा के नेता रविंदर रैना ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। उन्होंने सवाल किया कि जो लोग भारत-पाकिस्तान वार्ता के लिए लेटर लिख रहे हैं, क्या वे इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि पाकिस्तान भविष्य में कोई दुस्साहस या आतंकी कार्रवाई नहीं करेगा।

नजरिया

अजय कुमार
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

भारत-जापान की साझेदारी बदलेगी शक्ति समीकरण

भारत और जापान के रिश्तों की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि इनमें कभी उतार-चढ़ाव की राजनीति नहीं दिखी। 1952 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद दोनों देशों के बीच विश्वास लगातार बढ़ता गया। 2000 में रिश्तों को नई दिशा मिली, 2006 में उन्हें 'स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप' का दर्जा मिला और 2014 में इन्हें 'स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप' में बदल दिया गया। यह वही दौर था, जब जापान ने भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एशिया में सबसे भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखना शुरू किया। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, मेट्रो परियोजनाएं और औद्योगिक टाउनशिप जैसे दर्जनों बड़े प्रोजेक्ट इसी सोच का परिणाम हैं। जापान ने पिछले दो दशकों में भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया और आज करीब 1,400 जापानी कंपनियां भारतीय बाजार में सक्रिय हैं।

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को अपनी 'छोटी बहन' कहकर संबोधित किया, तब यह केवल शिष्टाचार का एक वाक्य नहीं था। कूटनीति की दुनिया में शब्द अक्सर दस्तावेजों से ज्यादा गहरे संदेश देते हैं। इस संबोधन के पीछे वह भरोसा छिपा था, जिसे भारत और जापान ने पिछले ढाई दशकों में धीरे-धीरे तैयार किया है। लेकिन इस मुलाकात की असली अहमियत भावनात्मक रिश्ते से कहीं आगे है। यह उस दौर में हुई है, जब एशिया की राजनीति नए मोड़ पर खड़ी है, चीन का बढ़ता दबदबा पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ा रहा है, वैश्विक सप्लाई चेन नए ठिकाने तलाश रही है और तकनीक भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ऐसे समय में भारत और जापान ने दुनिया को यह संकेत दिया है कि दोनों देशों की साझेदारी अब केवल निवेश और व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और सामरिक सुरक्षा की नई धुरी बनने जा रही है।

भारत और जापान के रिश्तों की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि इनमें कभी उतार-चढ़ाव की राजनीति नहीं दिखी। 1952 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद दोनों देशों के बीच विश्वास लगातार बढ़ता गया। 2000 में रिश्तों को नई दिशा मिली, 2006 में उन्हें 'स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप' का दर्जा मिला और 2014 में इन्हें 'स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप' में बदल दिया गया। यह वही दौर था, जब जापान ने भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एशिया में सबसे भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखना शुरू किया। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, मेट्रो परियोजनाएं और औद्योगिक टाउनशिप जैसे दर्जनों बड़े प्रोजेक्ट इसी सोच का परिणाम हैं। जापान ने पिछले दो दशकों में भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया और आज करीब 1,400 जापानी कंपनियां भारतीय बाजार में सक्रिय हैं।

लेकिन इस बार का शिखर सम्मेलन इसलिए अलग था क्योंकि पहली बार दोनों देशों ने रक्षा सह-विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब तक भारत और जापान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, रक्षा संवाद और समुद्री सुरक्षा तक सहयोग कर रहे थे, लेकिन रक्षा तकनीक के संयुक्त विकास की दिशा में यह पहला कदम है। इसका मतलब केवल हथियार बनाना नहीं है। इसका अर्थ है कि आने वाले वर्षों में दोनों देश ऐसी तकनीकों पर साथ काम करेंगे, जो समुद्री निगरानी, सुरक्षित संचार, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रक्षा प्रणाली और भविष्य की युद्ध तकनीकों की दिशा तय करेंगी। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत-जापान संबंधों का सबसे बड़ा रणनीतिक मोड़ मान रहे हैं, क्योंकि जापान लंबे समय तक रक्षा निर्यात और सैन्य तकनीक साझा करने में बेहद सतर्क रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं आया। इसके पीछे चीन की बढ़ती आक्रामकता सबसे बड़ा कारण है। पिछले एक दशक में दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, ताइवान के आसपास लगातार सैन्य अभ्यास, पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीपों को लेकर जापान के साथ तनाव और हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी ने पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था बदल दी है। दूसरी ओर, भारत भी पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लंबे सैन्य गतिरोध का सामना कर चुका है। ऐसे में नई दिल्ली और टोक्यो की रणनीतिक सोच पहले से कहीं ज्यादा समान दिखाई देती है। दोनों देश मानते हैं कि समुद्री रास्तों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान और नियम-आधारित व्यवस्था ही एशिया में स्थिरता बनाए रख सकती है। यही वजह है कि क्वाड के भीतर भी भारत और जापान सबसे सक्रिय साझेदारों में गिने जाते हैं।

रक्षा सहयोग के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा इस शिखर सम्मेलन का दूसरा सबसे बड़ा विषय रही। कोविड महामारी और उसके बाद रूस-यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को यह सिखाया कि केवल सस्ती सप्लाई चेन पर्याप्त नहीं होती, बल्कि भरोसेमंद साझेदार भी जरूरी होते हैं। लंबे समय तक दुनिया का अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन चीन पर निर्भर रहा, लेकिन अब अमेरिका, जापान, भारत और यूरोप वैकल्पिक सप्लाई नेटवर्क तैयार करने में जुटे हैं। इसी रणनीति के तहत भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और उन्नत विनिर्माण में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। आज दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था चिप्स पर टिकी है और जापान इस क्षेत्र में कच्चे माल, मशीनरी तथा तकनीक का बड़ा केंद्र है, जबकि भारत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का नया हब बन रहा है। दोनों देशों की साझेदारी भविष्य की तकनीकी प्रतिस्पर्धा में निर्णायक साबित हो सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान बताया कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के बीच लगभग 120 नए कारोबारी समझौते हुए हैं। अब लक्ष्य अगले दस वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन का जापानी निवेश आकर्षित करना है। भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत करीब छह लाख करोड़ रुपये से अधिक बैठती है। यह निवेश केवल कारखाने लगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल, बैटरी तकनीक और हाई-टेक उद्योगों में भी लगाया जाएगा। वर्ष 2025-26 में भारत-जापान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 27 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन दोनों सरकारें मानती हैं कि यह क्षमता के मुकाबले अभी भी काफी कम है। इसलिए अब निवेश और व्यापार दोनों को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी की जा रही है।

शिखर सम्मेलन में हरित ऊर्जा को भी नई प्राथमिकता मिली। 'गोवर्धन' पहल के तहत भारत-जापान बायोगैस मिशन शुरू किया गया है, जिसके जरिए आधुनिक बायोगैस संयंत्रों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसका मकसद केवल स्वच्छ ऊर्जा पैदा करना नहीं है, बल्कि कृषि अवशेषों का बेहतर उपयोग, किसानों की अतिरिक्त आय, जैविक उर्वरकों का उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना भी है। जापान की पर्यावरणीय तकनीक और भारत की विशाल कृषि अर्थव्यवस्था का यह मेल आने वाले वर्षों में ग्रामीण विकास का नया मॉडल बन सकता है। तकनीक के क्षेत्र में भी दोनों देशों की सोच तेजी से बदल रही है। अब सहयोग केवल हार्डवेयर या मशीनों तक सीमित नहीं रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, 6जी संचार, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भी संयुक्त अनुसंधान का रास्ता खोला गया है। जापान के पास उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग और सटीक विनिर्माण की क्षमता है, जबकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल प्रतिभा और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञता है। यदि दोनों की ताकतें एक मंच पर आती हैं, तो एशिया में तकनीकी नेतृत्व का नया केंद्र उभर सकता है।

2027 में भारत और जापान अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे करेंगे। लेकिन उससे पहले ही दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि आने वाला दशक केवल दोस्ती का नहीं, बल्कि साझा नेतृत्व का दशक होगा। बदलती वैश्विक राजनीति में, जहां कई पुराने गठबंधन कमजोर पड़ रहे हैं, वहीं भारत और जापान का रिश्ता लगातार मजबूत हो रहा है। यही वजह है कि नई दिल्ली में बोला गया 'छोटी बहन' का एक वाक्य केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि उस रणनीतिक विश्वास का प्रतीक बन गया, जिसके सहारे दोनों देश एशिया की नई शक्ति संरचना को आकार देने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह साझेदारी केवल भारत और जापान की नहीं, बल्कि पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की दिशा तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में गिनी जा सकती है।

उच्च शिक्षा व्यवस्था

डॉ. भूपेंद्र कुमार सुल्हेरे
लेखक स्तंभकार हैं।

क्या अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है?

'शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को जीवन, समाज और राष्ट्र के लिए सक्षम बनाना है। यदि डिग्री के बाद भी युवा रोजगार, कौशल और अवसर की तलाश में कतारों में खड़ा रहे, तो यह केवल शिक्षा की नहीं, पूरी व्यवस्था की विफलता है।' भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रही है, जहाँ अवसरों का विस्तार तो दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में विद्यार्थियों के सामने जटिलताओं का एक नया संसार खड़ा हो गया है। कभी विद्यालय से विश्वविद्यालय और फिर रोजगार तक की यात्रा अपेक्षाकृत सरल मानी जाती थी, परंतु आज यह यात्रा प्रवेश परीक्षाओं, माइक्रो-क्रेडेंशियल्स, ऑनलाइन प्रमाणपत्रों, स्किल सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, प्रतियोगी परीक्षाओं और अनेक प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अंतहीन श्रृंखला में बदल चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर नया दरवाज़ा सफलता की ओर नहीं, बल्कि एक और लंबी कतार की ओर खुलता है।

यह स्थिति उस भारत की कल्पना से भिन्न है जिसकी परिकल्पना नई शिक्षा नीति (एनईपी-2020) ने की थी। नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला, बहुविषयक, रोजगारोन्मुख और विद्यार्थी-केंद्रित बनाना था। किंतु व्यवहार में उच्च शिक्षा का स्वरूप ऐसा बनता जा रहा है जिसमें विद्यार्थी ज्ञान से अधिक प्रमाणपत्रों के संग्रह में उलझते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप शिक्षा का मूल उद्देश्य–व्यक्ति का बौद्धिक, व्यावसायिक और सामाजिक विकास–कहीं पीछे छूटता दिखाई देता है।

रोजगार का संकट: डिग्रियाँ बढ़ीं, अवसर नहीं

भारत विश्व का सबसे युवा देश है। प्रत्येक वर्ष लगभग 35 लाख इंजीनियर और 25 लाख अन्य विश्वविद्यालय स्नातक उच्च शिक्षा संस्थानों से निकलते हैं। इसके बावजूद लाखों शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में भटकते हैं। यह केवल बेरोजगारी का संकट नहीं, बल्कि रोजगारयोग्यता का संकट है। इस समस्या की ओर सबसे पहले 2005 में मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने ध्यान आकर्षित किया था। अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट "E&tending India's Leadership of the Global IT and BPO Industries" में संस्था ने बताया था कि भारतीय इंजीनियरिंग स्नातकों का बहुत छोटा हिस्सा ही बिना अतिरिक्त प्रशिक्षण के बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्य करने योग्य है। यह चेतावनी दो दशक पहले दी गई थी, किंतु आज भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।

मर्सर-मेटल स्किल्स इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय स्नातकों में केवल 42.6 प्रतिशत ही रोजगार योग्य हैं। वहीं इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025, जिसमें लगभग 65 लाख उम्मीदवारों का विश्लेषण किया गया, यह संकेत देती है कि लगभग आधे स्नातक आज भी उद्योग की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। इसका अर्थ स्पष्ट है-डिग्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण कौशल उसी अनुपात में विकसित नहीं हो रहे।

तीसरे वर्ष के बाद सबसे बड़ा शैक्षणिक शून्य

उच्च शिक्षा का तीसरा वर्ष विद्यार्थियों के लिए निर्णायक होना चाहिए। यही वह समय होता है जब उन्हें उद्योग, शोध, नवाचार, इंटर्नशिप और व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ना चाहिए। किंतु अधिकांश संस्थानों में यही सबसे कमजोर कड़ी है।

टीमलीज़ की एक व्यापक एडटेक रिपोर्ट, जिसमें देशभर के 1,071 उच्च शिक्षण संस्थानों का अध्ययन किया गया, बताती है कि केवल 9.68 प्रतिशत संस्थानों के पास सक्रिय उद्योग परियोजनाएँ उपलब्ध हैं। लगभग 37.8 प्रतिशत संस्थानों में इंटर्नशिप की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है, जबकि मात्र 9.4 प्रतिशत संस्थानों में सभी कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप लागू है। उद्योग विशेषज्ञों की नियमित भागीदारी केवल 23.02 प्रतिशत संस्थानों तक सीमित है और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जैसी अवधारणा अभी भी अधिकांश संस्थानों में अनुपस्थित है।

ऐसी स्थिति में विद्यार्थी डिग्री तो प्राप्त कर लेते हैं, किंतु वास्तविक कार्यस्थल की चुनौतियों और व्यावसायिक अपेक्षाओं के लिए तैयारनहीं हो पाते।

पाठ्यक्रम और उद्योग के बीच बढ़ती खाई

भारतीय उच्च शिक्षा की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक पाठ्यक्रम और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच बढ़ता अंतर है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार केवल 8.6 प्रतिशत संस्थानों में पाठ्यक्रम पूरी तरह उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप है। लगभग आधे संस्थानों ने स्वीकार किया कि उनके पाठ्यक्रमों में उद्योग की अपेक्षाओं का कोई प्रभावी समावेश नहीं है। वहीं 60 प्रतिशत से अधिक संस्थान उद्योग-मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्रों को अपने नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं बनाते।

जब उद्योग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और नवाचार जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं की मांग कर रहा है, तब अनेक विश्वविद्यालय वर्षों पुराने पाठ्यक्रमों पर आधारित शिक्षा दे रहे हैं। यही कारण है कि विश्वविद्यालयों से निकलने वाले अनेक स्नातकों को रोजगार मिलने से पहले अतिरिक्त प्रशिक्षण लेना पड़ता है।

डिग्री नहीं, कौशल की मांग

आज का नियोक्ता केवल अंकतालिका नहीं देखता। वह संचार क्षमता, समस्या समाधान, टीमवर्क, नेतृत्व, समय प्रबंधन, डिजिटल दक्षता और विश्लेषणात्मक सोच जैसे कौशलों को प्राथमिकता देता है।

फिर भी केवल लगभग 36 प्रतिशत संस्थानों में इन सॉफ्ट स्किल्स को व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जाता है। अंग्रेज़ी संचार, लेखन, प्रस्तुतिकरण और व्यावसायिक व्यवहार जैसे आवश्यक कौशलों की कमी के कारण अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी रोजगार की दौड़ में पीछे रह जाते हैं।

पूर्व छात्र: सबसे मजबूत कड़ी, सबसे कमजोर व्यवस्था

विश्वविद्यालयों के पूर्व छात्र (Alumni) उद्योग और शिक्षा के बीच सबसे प्रभावी सेतु हो सकते हैं। वे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन, मेंटरशिप, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। दुर्भाग्यवश केवल 5.44 प्रतिशत संस्थानों में ही पूर्व छात्रों की सक्रिय भागीदारी है। अधिकांश विश्वविद्यालय इस अमूल्य संसाधन का प्रभावी उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं।

प्रवेश परीक्षाओं का बढ़ता संकट

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) का गठन प्रवेश परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से किया गया था। किंतु पिछले कुछ वर्षों में अनेक परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक, तकनीकी त्रुटियाँ, परिणामों में विलंब और न्यायालयी हस्तक्षेप जैसी घटनाओं ने इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

NEET-UG, NEET-PG, UGC-NET, CSIR-NET, CUET ÌÍæ JEE Main जैसी परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित किया। प्रवेश परीक्षाएँ, जो कभी अवसर का माध्यम थीं, अब अनेक विद्यार्थियों के लिए तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता का कारण बन गई हैं।

असमानता की नई दीवारें

ऑनलाइन शिक्षा, माइक्रो-क्रेडेंशियल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म आधुनिक अवश्य हैं, लेकिन उनकी पहुँच समान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी, क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन करने वाले युवा तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र महंगे प्रमाणपत्रों, सीमित इंटरनेट सुविधा और कमजोर डिजिटल आधारभूत संरचना के कारण पीछे छूट जाते हैं। महिलाओं की रोजगार क्षमता में आई गिरावट भी इस असमानता को और स्पष्ट करती है।

समाधान की दिशा

यदि भारत को वास्तव में ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनना है, तो उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार अनिवार्य हैं। राष्ट्रीय डिजिटल क्रेडेंशियल वॉलेट, सरल क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली, माइक्रो-क्रेडेंशियल्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली स्वतंत्र व्यवस्था, उद्योग के साथ मिलकर पाठ्यक्रम निर्माण, सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप, एनटीए में संस्थागत सुधार, सार्वजनिक ब्रिजिंग कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालय-उद्योग-पूर्व छात्र साझेदारी जैसे कदम अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुके हैं। बीस वर्ष पहले मैकिन्से की चेतावनी केवल एक आँकड़ा नहीं थी, बल्कि भविष्य का संकेत थी। आज भी यदि लगभग आधे स्नातक रोजगार योग्य नहीं हैं, अधिकांश संस्थान उद्योग की अपेक्षाओं से कटे हुए हैं और प्रवेश परीक्षाएँ स्वयं संकट का विषय बन गई हैं, तो यह केवल शिक्षा व्यवस्था का नहीं, बल्कि राष्ट्र के विकास मॉडल का प्रश्न है।

भारत को यह निर्णय लेना होगा कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियाँ वितरित करना है या ऐसे सक्षम, नवाचारी और आत्मनिर्भर नागरिक तैयार करना है जो बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकें।

शिक्षा तब सफल मानी जाएगी, जब प्रत्येक नया प्रमाणपत्र एक नए अवसर का द्वार खोले, न कि एक और लंबी कतार में खड़ा होने की मजबूरी बने। यही भारतकी उच्च शिक्षा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

सुरेश रायकवार
लेखक व्यंग्यकार हैं।

बेरोजगारी की चिंता युवाओं से अधिक हमारे नेताओं को

'एक अनार और सौ बीमार,' आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, हमारे देश में सरकारी नौकरी और बेरोजगारी के लिए यह कहावत सौ प्रतिशत सही है। एक अनुमान के आधार पर हमारे देश में निजी और सरकारी क्षेत्र को मिलाकर कुल नौकरियाँ 15 करोड़ के लगभग हैं, जिनमे से केंद्र और राज्य सरकारों की नौकरियाँ अनुमानतः 1.5 करोड़ के आसपास आँकी जाती हैं। इस मान से सौ नौकरियों में से केवल एक नौकरी सरकारी है, तो हुए ना एक अनार और सौ बीमार। और इसीलिए देखने में आता है कि जब एक मामूली से चपरासी और सिपाही की भर्ती का विज्ञापन निकलता है तो एक-एक पोस्ट के लिए हजारों उम्मीदवार आवेदन करते हैं। इनके चयन के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें सरकारों के पसीने छूट जाते है साथ ही परीक्षा का पर्चा लीक होने का डर अलग! कभी-कभी तो परीक्षार्थियों की भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि ये परीक्षा देने नहीं बल्कि रेल रोकने अथवा पुलिस से मुठभेड़ के लिए ही एकत्र हुए हैं, किसी-किसी को तो इनकी यह भीड़ काकरोचों जैसी भी लगती है। और शायद इसी कारण कई सरकारें तो, पदों पर रिक्तियाँ होने के बावजूद वर्षों-तक परीक्षाएँ ही नहीं करवाती हैं।

अर्थशास्त्र का एक नियम है कि जो वस्तु मात्रा में जितनी कम होगी बाजार में उसकी मांग उतनी ही अधिक होगी, हमारे देश में उपलब्ध सरकारी नौकरियों पर भी यही नियम लागू होता है। सरकारी नौकरी का महत्व इसलिए भी अधिक होता है कि उसमे वेतन भले ही कम हो किन्तु ऊपर की कमाई आपकी क्षमता अनुसार रहती है, तभी तो कभी-कभार लोकायुक्त के छापों में चपरासी और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के यहाँ से भी करोड़ों रुपये जब्त होते हैं, फिर अधिकारियों की तो बात ही क्या। सरकारी नौकर का समाज में मान सम्मान और रुतबा अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसीलिए सरकारी नौकरी वाले दूल्हों की मांग भी अधिक होती है और उनकी दहेज वैल्यू भी।

हमारी मानसिकता ही कुछ ऐसी हो गई है कि हम अपने बच्चों को तो प्रायवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, यात्रा के लिए प्रायवेट बसें चाहिए, हवाई यात्रा के लिए प्रायवेट कंपनी के विमान चाहिए और बीमार होने पर अपना इलाज भी प्रायवेट अस्पताल में ही करवाना चाहते है, किन्तु देश के हर बेरोजगार को नौकरी केवल और केवल सरकारी चाहिए, उसके लिए चाहे पुश्तैनी जमीन बेचना पड़े या भारी-भरकम रिश्वत ही क्यों ना देना पड़े। यहाँ तक कि जब लड़की की शादी करना हो, तो लड़का भी सरकारी नौकरी वाला ही ढूंढा जाता है। स्वतन्त्रता के बाद पढ़ाई-लिखाई के कारण देश के युवाओं का स्टैंर्ड्डर्ड थोड़ा ऊंचा हो गया है, इसलिए वे ना तो कोई पैतृक धंधा करना चाहते हैं ना ही खेती-बाड़ी का काम, यहाँ तक की वे छोटे-मोटे प्रायवेट-जॉब को तो रोजगार ही नहीं मानते हैं। अब इतना पढ़ें है तो कम-से-कम सरकारी नौकरी तो होना ही चाहिए ना! या लाखों के पैकेज वाली प्राइवेट नौकरी! वरना क्या काम की ये पढ़ाई लिखाई। अब सबकी किस्मत तो ऐसी नहीं होती कि उन्हे अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा गिनने का काम मिल जाए!

अब यह तो हमारी सरकारों की ही गलती मानी जाएगी ना कि उन्होने पहले तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई और ऊपर से युवाओं को शिक्षा ऋण दे-देकर ऊंची पढ़ाई करवा दी। अब पढ़ाई के बाद भी क्या कोई खेती जैसा निकृष्ट कार्य करेगा? या अपना पुश्तैनी धंधा ही चलाता रहेगा ? सरकार को चाहिए कि हर पढ़े-लिखे युवा के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करे। देश के धंधे और खेती का कार्य तो देश में पैर जमा चुकीं विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियाँ ही संभाल लेंगी।

प्राचीन समय में तो हमारे देश में नौकरी को अच्छा भी नहीं माना जाता था। और शायद इसीलिए, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर महाकवि घाघ द्वारा रचित कहावत दोहराया करते थे - 'उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान।' किन्तु आज तो इसके उलट सरकारी नौकरी पाने के लिए युवा क्या-क्या नहीं कर रहा है। कोई स्नातक अपने आप को आठवीं पास बताकर चपरासी की नौकरी कर रहा है तो कोई इंजीनियरिंग का स्नातक लिपिक बनकर अपने आप को धन्य समझ रहा है। कोई अजा/अजजा के झूठे प्रमाण पत्र लगा कर नौकरी पाने की जुगाड़ करता नजर आता है तो कई उच्च शिक्षित युवा, सरकारी विभागों के निम्न स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रहे है।

बेरोजगारी की चिंता बेरोजगारों से अधिक हमारे राजनैतिक दलों के नेताओं को होती है, चुनाव की सुगबुगाहट आरंभ हुई नहीं कि नेता बेरोजगारी-बेरोजगारी चिल्लाने लगते है। कोई इसे सरकार की असफलता बतलाता है तो कोई आज तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी निरूपित करता है, कोई सत्ता में आने पर सौ प्रतिशत बेरोजगारी समाप्त करने की गारंटी देता है तो कोई बेरोजगारी भत्ते बढ़ाने का आश्वासन देकर लुभाते नजर आता हैं। यहाँ तक कि जो क्षेत्रीय पार्टी मात्र 10-20 सीट पर आम-चुनाव लड़ रही है वह भी अपने चुनावी घोषणा-पत्र में पूरे देश से बेरोजगारी समाप्त करने का वचन देती है।

हमारे देश में बेरोजगारी के इस भीषण-काल में संभवतः बेरोजगारों को धैर्य बंधाने के लिए ही देश के एक महान संत लिख गए है-

अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम।
दास मलूका कह गए, सबके दाता राम।।

प्लास्टिक वस्तुओं से छुटकारा पाने की दरकार

भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधों को कठोर किया जाता है। स्थानीय प्रशासनिक स्तरीय सतर्कता भी बढ़ाई जाती है। पर, ये सख्तियां एकाध महीने चलती हैं, उसके बाद फिर से प्लास्टिक बैगों का प्रयोग लोग शुरू कर देते हैं। भारत में प्रतिदिन करीब 25 से 26 हजार टन प्लास्टिक कचरा बनता है। प्लास्टिक कचरे के चलते जहरीले माइक्रोप्लास्टिक से फैलने वाली बीमारियों से सालाना लाखों लोगों की असमय मौत होती हैं। प्लास्टिक कचरे से 'डायऑक्सिन' और 'फयूरान' जैसी जहरीली व जानलेवा गैसों के निकलने से कैंसर का खतरा, तव्चा संबंधी बीमारियां का बढ़ना और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। भारत में 145 करोड़ जनसंख्या के चलते प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने में हम अव्वल स्थान पर हैं। सालाना 94 लाख टन कचरा बनता है। पिछले 5 वर्षों में इसमें तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसपर ईमानदारी से विमर्श करना होगा।

विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस

डॉ.रमेश ठाकुर

सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, भारत सरकार

'सिंगल यूज प्लास्टिक' का प्रयोग इंसानी जीवन शैली में दिनों-दिन बढ़ रहा है। ये ऐसी मानवीय हिमाकत है जिसमें नुकसानों की सीमाएं असीमित हैं। प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं के इस्तेमाल से मानव जीवन और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए ही सालाना 3 जुलाई को समूचे संसार में 'विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस' मनता है। दिवस का आज 17वां संस्करण मनाया जा रहा है। शुरूआत वर्ष-2009 में जीरो वेस्ट यूरोप द्वारा हुई थी। रोजमर्रा की जरूरतों में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक वस्तुओं का चलन बीते कुछ वर्षों से सर्वाधिक बढ़ा है। डब्ल्यूएचओं की रिपोर्ट के मुताबिक 'प्लास्टिक पॉल्यूशन' के चलते सालाना विश्वभर में 4 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं और 3 करोड़ से अधिक बेजुआन जानवरों की मौतें होती हैं। हास्यास्पद ये है कि विश्व के विभिन्न देशों के साथ-साथ भारत के तमाम राज्यों में इस वक्त भी प्लास्टिक बैग, थैलियां, सिंग यूज प्लास्टिक सामान प्रतिबंधित हैं। बावजूद इसके इनका प्रयोग धड़ल्ले से जारी है। भारत में प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियों की भरमार है। सबसे पहले इन्हें बंद किया जाना चाहिए।

भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधों को कठोर किया जाता है। स्थानीय प्रशासनिक स्तरीय सतर्कता भी बढ़ाई जाती है। पर, ये सख्तियां एकाध महीने चलती हैं, उसके बाद फिर से प्लास्टिक बैगों का प्रयोग लोग शुरू कर देते हैं। भारत में प्रतिदिन करीब 25 से 26 हजार टन प्लास्टिक कचरा बनता है। प्लास्टिक कचरे के चलते जहरीले माइक्रोप्लास्टिक से फैलने वाली बीमारियों से सालाना लाखों लोगों की असमय मौत होती हैं। प्लास्टिक कचरे से 'डायऑक्सिन' और 'फयूरान' जैसी जहरीली व जानलेवा गैसों के निकलने से कैंसर का खतरा, तव्चा संबंधी बीमारियां का बढ़ना और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। भारत में 145 करोड़ जनसंख्या के चलते प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने में हम अव्वल स्थान पर हैं। सालाना 94 लाख टन कचरा बनता है। पिछले 5 वर्षों में इसमें तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसपर ईमानदारी से विमर्श करना होगा।

सरकारों को प्लास्टिक प्रतिबंधों पर और सख्ती दिखानी होगी। साथ ही भारी-भरकम हर्जाने का प्रावधान भी करने की दरकार है। इसके अलावा दैनिक जीवन शैली में प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बगैर सामाजिक चेतना के यह अभियान सफल नहीं होने वाला। इसके लिए सरकारों को संचार माध्यमों और प्रचार-प्रसार विधाओं पर और जोर देना होगा। जनजन को प्लास्टिक के दुष्परिणामों को बताना होगा। आने वाली पीढ़िया कैसा बर्ताव करें, ये भी बताना होगा। सबसे जरूरी कदम सरकारी प्रयासों में प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प को जनता में मुहैया करवाने का रहेगा। ऐसा करने के बाद ही लोग प्लास्टिक बैगों की उपयोगिता कम कर पाएंगे। बैगों के अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स, खानपान के पैकेट, बाजारी वस्तुओं की पैकेजिंगों में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल खूब होने लगा है। प्लास्टिक सिर्फ इंसानों के लिए ही घातक नहीं है, बेजुबान जानवरों और पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। देश-विदेश में फैले प्रदूषण में भी प्लास्टिक अव्वल भूमिका निभा रहा है।

हिंदुस्तान में 'प्लास्टिक मुक्त भारत' का सपना केवल नारा नहीं, बल्कि एक जरूरी लक्ष्य भी है, जो पर्यावरण और भविष्य की सुरक्षा की परवाह करता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित चीजें ना सिर्फ जलाशयों को गंदा करती हैं, बल्कि नंदी, तालाब, पौखर, झील-झरनों को भी दूषित कर रही हैं। प्लास्टिक वस्तुओं के प्रदूषण से जलीय जीवों के जीवन को भी खतरा बढ़ा है। रोजाना सैकड़ों क्विंटल प्लास्टिक बैग-थैलियों को लोग समुदों और नदियों में फेंकते हैं, उनको भोजन समझकर निगलने के बाद जलीय जीव बेमौत मर जाते हैं। आवारा पशुओं का प्लास्टिक खाकर मरना तो अब आम बात हो गई है। प्लास्टिक वस्तुओं के जीवित रहने की मियाद एकाध साल नहीं होती, बल्कि 4 से 5 सौ साल तक नष्ट नहीं होती। प्लास्टिक बैग मुक्त को वैश्विक स्तर पर मनाने के पीछे उद्देश्य एकमात्र जनमानस को इसके खतरों से वाकिफ करवाना और आगाह करना होता है। इंसानी लाइफस्टाइल से अगर प्लास्टिक का छुटकारा नहीं हुआ, तो उसके दुष्परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। प्लास्टिक वस्तुओं की जगह हम जूट, कपड़ें और कागजों से बने बैग्स और थैलियों का प्रयोग कर सकते हैं।

प्लास्टिक कचरा जमीन और पानी दोनों को गंदा करने लगा है। प्लास्टिक मुक्त अभियान को हमें अपनाना होगा। बाजारों में खरीददारी के लिए हमें कपड़े या कागज के थैलों को इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही दूसरों को भी प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों से अवगत करवाना चाहिए। वैश्विक सरकारें प्लास्टिक के पुनर्चंकरण यानी रिसाइक्लिंग पर विचार करके समस्या का मुकम्मल समाधान निकाल सकती हैं। हालांकि, इस दिशा में भारत सरकार ने 2016 से कदम बढ़ाए हुए हैं। प्लास्टिक वस्तुओं को नष्ट करके उनका दोबारा प्रयोग में लाने की आधुनिक तकनीकों के जरिए करना आरंभ किया हुआ है। इसके लिए बाकायदा हैदराबाद और गुजरात में प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। पर्यावरण सुरक्षा का मुद्दा इंसानी जीवन के अस्तित्व से जुड़ा विषय है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। साथ ही जनमानस को भी अपनी भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभानी होगी। प्लास्टिक वस्तुओं से तौबा करना होगा। प्लास्टिक के विकल्पों को अपनाना होगा। तभी भारत में रोजाना 26000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होने में कमी लाई जा सकेगी।

मानव सभ्यता को प्रकृति की अंतिम चेतावनी

इस वर्ष यूरोप के अनेक देशों स्पेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, ग्रीस और बाल्कन क्षेत्र का तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँच गया। अनेक स्थानों पर दशकों पुराने तापमान के रिकॉर्ड टूट गए। लोगों को दोपहर में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण के मरीज बढ़ने लगे। स्कूलों के समय बदले गए और खुले स्थानों पर कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए विशेष सुरक्षा निर्देश जारी करने पड़े। यह दृश्य उस यूरोप का नहीं लगता जिसे कभी शीतलता और सौम्यता का प्रतीक माना जाता था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार भीषण गर्मी के पीछे 'ओमेगा ब्लॉक' नामक वायुमंडलीय स्थिति भी एक प्रमुख कारण है। इसमें उच्च वायुदाब का क्षेत्र लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रहता है और ठंडी हवाओं के प्रवेश को रोक देता है। परिणामस्वरूप गर्म हवा उसी क्षेत्र में फँसी रहती है और तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है।

यूरोप की गर्मी

रागिनी श्रीवास्तव

लेखिका कनाडा निवासी साहित्यकार हैं।

'जब प्रकृति अपना संतुलन खोने लगती है, तब सबसे पहले मौसम बदलता है और अंततः मानव का भविष्य।'

भारतीय संस्कृति सदियों से प्रकृति को पूजनीय मानती रही है। ऋग्वेद में पृथ्वी को माता कहा गया है

'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' अर्थात् 'पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं।'

यदि हम इस सांस्कृतिक दृष्टि को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ दें, तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना कठिन नहीं होगा।

कभी यूरोप का नाम सुनते ही मन में बर्फ से ढकी पर्वत-श्रृंखलाएँ, हरी-भरी घाटियाँ, ठंडी हवाएँ और सुहावनी गर्मियाँ उभर आती थीं। वहाँ की जलवायु को दुनिया की सबसे संतुलित जलवायु माना जाता था। परंतु आज वही यूरोप भीषण गर्मी की ऐसी लपटों में घिरा है कि सड़कें तप रही हैं, नदियों का जलस्तर घट रहा है, जंगल धधक रहे हैं और लाखों लोगों का दैनिक जीवन संकट में पड़ गया है। यह केवल मौसम का उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि बदलती जलवायु की वह दस्तक है जिसे अब अनसुना करना संभव नहीं।

इस वर्ष यूरोप के अनेक देशों स्पेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, ग्रीस और बाल्कन क्षेत्र का तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँच गया। अनेक स्थानों पर दशकों पुराने तापमान के रिकॉर्ड टूट गए।

लोगों को दोपहर में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण के मरीज बढ़ने लगे। स्कूलों के समय बदले गए और खुले स्थानों पर कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए विशेष सुरक्षा निर्देश जारी करने पड़े। यह दृश्य उस यूरोप का नहीं लगता जिसे कभी शीतलता और सौम्यता का प्रतीक माना जाता था।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार भीषण गर्मी के पीछे 'ओमेगा ब्लॉक' नामक वायुमंडलीय स्थिति भी एक प्रमुख कारण है। इसमें उच्च वायुदाब का क्षेत्र लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रहता है और ठंडी हवाओं के प्रवेश को रोक देता है। परिणामस्वरूप गर्म हवा उसी क्षेत्र में फँसी रहती है और तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है। आज पृथ्वी का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ चुका है। जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, वनों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ते उद्योग, वाहनों से निकलने वाली गैसें और अनियंत्रित शहरीकरण ने वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ा दी है। परिणामस्वरूप पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा अंतरिक्ष में पूरी तरह नहीं जा पाती और वातावरण लगातार गर्म होता जा रहा है। यही कारण है कि कभी दुर्लभ मानी जाने वाली हीट वेव आज लगभग हर वर्ष नई तीव्रता के साथ लौट रही है।

यूरोप की यह गर्मी केवल तापमान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही, बल्कि जीवन के अनेक आयामों को प्रभावित कर रही है। जंगलों में आग की घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं। हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र राख में बदल रहे हैं। अनेक वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास खो रहे हैं। कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। नदियों और जलाशयों का जलस्तर गिर रहा है। जलविद्युत उत्पादन घट रहा है। बिजली की माँग बढ़ने से ऊर्जा व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है।

कूड़े की गंध: समाज की सड़ांध पर तंज

साहित्य

पद्माकर पागे

समीक्षक

कहानीकार इंदू सिन्हा की कहानी 'कूड़े की गंध' को साहित्य समर्था प्रतियोगिता जयपुर में 2026 में श्रेष्ठ कहानी के रूप में पुरस्कृत किया गया है। यह कहानी सामाजिक व्यवस्थाओं पर तंज करती है। इंदू सिन्हा की इस कहानी से गुजरते हुए कई विचार एक साथ मन में आते हैं। पेट, परिस्थितियां और मजबूरियां जीवन में क्या-क्या करवा लेंगी कहना कठिन है। कौन नहीं चाहता कि दो रोटियां सुख-शांति से मिले पर ऐसा होता नहीं है। रोटी के लिए कई संघर्ष करने पड़ते हैं, तडपना पड़ता है। मेहनत करना पड़ती है। तब नसीब होती है रोटी। 'कूड़े की गंध' कहानी की मुख्य पात्र गुलाबों की जिंदगी भी कुछ ऐसी है। सुबह से कचरा बीनना, छांटना और कबाड़ी के यहां देना। शाम को जो सौ पचास रूपये मिले उससे नोन, तेल, लकड़ी की व्यवस्था करना। यहां तक तो ठीक है, गुलाबों तिरछी और कामुक नजरों से देखने वाले इस पुरूष प्रधान समाज में है। एक मोटा चायवाला भी इस कहानी का पात्र है। उसकी नजर गुलाबो पर है और अपनी हरकतों से चाय देते समय हाथ पकड़ना, टल्ला मारना, तंज कसना आम बात हैं। उसे गुलाबों को अपनी ओर आकर्षित करना है और किसी भी तरह उसे पाना है। गुलाबो भी उससे मन ही मन चाहती तो है उसकी सहेलियों के मना करने के बाद भी चाय पीने तो सहेलियों के साथ टपरी पर ही जाती है। अच्छा और सुंदर जीवन जीने की गुलाबो की इच्छा और मोटाबाबू की हरकतें उनको संयोग से साथ ले ही आती हैं। मोटा का कहना कि क्यों सौ-पचास के लिए दिनभर भटकना? मेरा साथ दे तुझे वैसे ही मालामाल कर दूंगा। मजबूरी में गुलाबो यहीं आकर मात खा जाती है और वह अपना सर्वस्व दे बैठती है।

कहानी यही खत्म नहीं होती। समाज में शोषण करने वाले कई हैं। हर आदमी यह कर रहा है। गरीब हमेशा ऐसा ही पिसता रहेगा, शोषण होता रहेगा। आज भी सुबह-सुबह कचरे की गाड़ियों के पीछे अपना झोला लटकाए कई गुलाबो दौडती दिख जाएगी। प्रश्न है कि कहानी का दुःखद अंत गुलाबो जैसे जेल की चार दिवारों में जीवन बीताते हुए ही होगा क्योंकि उसके नाजायज सम्बंधों से पैदा हुए बच्चे को कुड़े के ढेर पर फेंकने का अपराध किया है। इंदु सिन्हा ने बहुत स्पष्ट शब्दों अपनी बात रखने का साहस किया है और यह कहानी की आवश्यकता भी है। भविष्य में ऐसी ही सामाजिक विषमता लिए कहानी की अपेक्षा रहेगी।

पुणे की त्रासदी समाज का कड़वा सच

कुछ समय से मीडिया के पन्नों और पुलिस की फाइलों में एक बेहद विचलित करने वाली प्रवृत्ति बार-बार सामने आ रही है, जहां जीवनसाथी या मंगेतर की हत्या में पत्नियों और मंगेतरों की सीधी संलिप्तता पाई जा रही है। इस खौफनाक सिलसिले का सबसे ताजा और रूह कंपा देने वाला उदाहरण पुणे के पास ऐतिहासिक लोहगढ़ किले में देखने को मिला। यहां सिया गोयल नाम की युवती ने अपने नए नवेले मंगेतर केतन अग्रवाल को अपनी राह का रोड़ा समझा और अपने प्रेमी को पाने की अंधाधुंध चाहत में उसे किले की ऊंची और ढलान भरी पहाड़ियों से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जब इस साजिश की परतों को उजागर कर रही है, तो सामने आ रहा सच किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोरने के लिए काफी है।

रिश्तों का कुरुक्षेत्र

एकता शर्मा

(कानूनी और सामाजिक विशेषज्ञ)

पुणे में सिया गोयल में जो हुआ वो घटना कोई अपवाद नहीं है। बल्कि, यह देश के महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक फैली उस गहरी सामाजिक विकृति का प्रतीक है, जिसे अब एक गंभीर सामाजिक संकट के रूप में विश्लेषित करने की आवश्यकता है। पुणे का यह मामला इसलिए ज्यादा डरावना है, क्योंकि यह विश्वास और धोखे की पराकाष्ठा है। जिस मंगेतर के साथ सिया गोयल ने भविष्य के सपने बुनने का दिखावा किया, उसी को उसने एक बेहद सुनियोजित साजिश के तहत ट्रेकिंग के बहाने लोहगढ़ किले पर बुलाया। एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वह एक कत्लगाह में बदल गया। यह वारदात किसी आवेश का परिणाम नहीं थी, बल्कि ठंडे दिमाग से तैयार की गई एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसमें प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग की गई थी ताकि समाज की नजरों में यह महज एक 'एक्सीडेंट' या पैर फिसलने की घटना लगे।

पुलिस की तफ्तीश में जब परतें खुलीं, तो पता चला कि आधुनिकता और निजी स्वतंत्रता की आड़ में किस तरह एक इंसानी जिंदगी को कचरे की तरह फेंक दिया गया। यह घटना बताती है कि आज के दौर में रिश्तों की पवित्रता और किसी की जान की कीमत कितनी सस्ती हो चुकी है। आमतौर पर यह माना जाता रहा है कि इस तरह के जटिल, ठंडे दिमाग से रची गई साजिश वाले अपराध केवल मुंबई, दिल्ली या पुणे जैसे महानगरों की भागदौड़ भरी, अजनबी और तनावग्रस्त जिंदगी का हिस्सा होते हैं। लेकिन इस मामले के संदर्भ में जब हम देश के अन्य हिस्सों पर नजर डालते हैं, तो स्थिति और भी चिंताजनक दिखती है।

पुणे और इंदौर जैसे विकसित शहर से लेकर सिंगरौली और भिंड जैसे छोटे शहरों के ग्रामीण अंचलों तक, सोनम, रूबी, उमा और प्रियंका जैसी कई कहानियां बिखरी पड़ी हैं। छोटे कस्बों में आज भी सामाजिक दबाव और रूढ़िवादिता के कारण जब शादियां तय कर दी जाती हैं, या बेमेल रिश्ते थोप दिए जाते हैं, तो आधुनिक संचार माध्यमों के दौर में वे रिश्ते एक घातक त्रिकोण में बदल जाते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने गांवों और शहरों की भौगोलिक दूरी को तो मिटा दिया है, लेकिन साथ ही इसने ग्रामीण परिवेश में भी वही मानसिक विकृतियां पैदा कर दी हैं जो पहले शहरी समाज की विसंगतियां मानी जाती थीं। पुणे के इस ताजा मामले में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है, वह है अपराध को अंजाम देने का तरीका। जहर देना या सीधे हमला करने के बजाय एक ऐसी जगह को चुनना जहां दुर्घटना का बहाना आसानी से बनाया जा सके, यह अपराधियों की बढ़ती शातिर मानसिकता को दर्शाता है।

आज का अपराधी वर्ग, विशेषकर इस तरह की साजिशों में शामिल महिलाएं, इंटरनेट, सोशल मीडिया और क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज से प्रभावित हो रहे हैं। वे कानून की कमियों और सबूत मिटाने के तरीकों को स्क्रीन पर देखकर अपनी असल जिंदगी में आजमाने की कोशिश करते हैं। प्यार या वासना के अंधेपन में डूबे ये लोग यह भूल जाते हैं कि डिजिटल पदचिह्न और पुलिस की फॉरेंसिक जांच अंततः सच को सामने ले ही आती है। कानून से बचने का यह भ्रम उन्हें इस हद तक अंधा कर देता है कि वे उस व्यक्ति की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते जिसे समाज ने उनका जीवनसाथी चुना था।

भारतीय समाज में विवाह को केवल दो व्यक्तियों का कानूनी समझौता नहीं, बल्कि सात जन्मों का एक पवित्र आत्मिक बंधन माना गया है। लेकिन वैश्वीकरण और अनियंत्रित आकांक्षाओं के इस दौर में इस संस्था की नींव हिलती दिख रही है। आज व्यक्तिवाद और तात्कालिक सुख की चाहत इतनी हावी हो चुकी है कि लोग धैर्य, समझदारी और त्याग जैसे पारंपरिक मूल्यों को बोझ समझने लगे हैं। जब रिश्तों में भावनात्मक शून्यता आ जाती है, तो वहां अविश्वास और अकेलापन पनपने लगता है। ऐसी स्थिति में, यदि कोई तीसरा व्यक्ति जीवन में प्रवेश करता है, तो वह कमजोरी एक बड़ी विभीषिका का रूप ले लेती है। महिलाएं जब अपने वैवाहिक जीवन या तय हो चुके रिश्तों में फंसा हुआ महसूस करती हैं और उन्हें बाहर निकलने का कोई सम्मानजनक रास्ता दिखाई नहीं देता, जैसे समाज में आज भी सगाई टूटने या तलाक को एक कलंक के रूप में देखा जाता है, तो वे इस सामाजिक बदनामी से बचने के लिए सीधे अपराध का खौफनाक रास्ता चुन लेती हैं।

पुणे के लोहगढ़ किले से गिराकर की गई यह हत्या महज एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यह इस बात का अलार्म है कि हम अपनी नई पीढ़ी को किस तरह के संस्कार, नैतिक मूल्य और मानसिक स्वास्थ्य दे रहे हैं। यदि समय रहते इस सामाजिक पतन को नहीं रोका गया, तो आने वाले समय में विवाह और सगाई जैसी संस्थाएं अपना विश्वास पूरी तरह खो देंगी। इस समस्या का समाधान केवल पुलिसिया कार्रवाई या सख्त कानूनों से संभव नहीं है। इसके लिए एक सामूहिक सामाजिक आंदोलन और सोच में बदलाव की जरूरत है। हमें अपने परिवारों के भीतर संवाद को फिर से जीवित करना होगा। विवाह से पहले और बाद में काउंसलिंग जैसी व्यवस्थाओं को समाज में सामान्य बनाना होगा ताकि यदि कोई जोड़ा आपसी तालमेल नहीं बिठा पा रहा है या वे इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो वे हिंसा या हत्या का मार्ग चुनने के बजाय कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से अलग होने का साहस जुटा सकें। समाज को भी अपनी सोच लचीली करनी होगी ताकि कोई भी व्यक्ति सामाजिक लोकलाज के डर से इतना मजबूर न हो जाए कि वह सीधे अपराधी बन बैठे। यह समय सनसनी फैलाने का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का है, ताकि भविष्य में किसी और मासूम को अपनों की ही साजिश का शिकार होकर लोहगढ़ जैसी ढलानों पर अपनी जान न गंवानी पड़े।

रूपाखेड़ा, नाहरखेड़ा, तिलगारा के किसान उच्च गुणवत्ता वाले फूल जरबेरा, लिथियन्सन, जिप्सोफिला, कश्मीरी गुलाब के साथ हाई-वैल्यू फसल ब्लूबेरी की खेती कर रहे हैं

संभागायुक्त डॉ सुदाम खाड़े ने धार जिले में आधुनिक उद्यानिकी को नजदीक से देखा

धार। कमिश्नर सुदाम खाडे ने बदनावर विकासखंड का दौरा कर उन्नत कृषि तकनीक एवं जिले में किए जा रहे नवाचारों का अवलोकन किया। भ्रमण का मुख्य उद्देश्य किसानों के नवाचारों को प्रोत्साहित करना था। संभाग आयुक्त ने ग्राम रूपाखेड़ा, नाहरखेड़ा और तिलगारा में पॉली हाउस और शेडनेट हाउस का निरीक्षण किया, जहाँ किसान उच्च गुणवत्ता वाले फूलों जैसे गुलाब, जरबेरा, लिथियन्सन, जिप्सोफिला और कश्मीरी गुलाब के साथ-साथ 'हाई-वैल्यू' फसल 'ब्लूबेरी' की खेती कर रहे हैं।

निरीक्षण के दौरान उप संचालक उद्यानिकी विभाग नीरज सावलिया ने बताया कि जिले में वर्तमान में लगभग 1,86,589 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापित हैं, जिनका लाभ

75 से अधिक प्रगतिशील किसान उठा रहे हैं। किसानों के साथ संवाद करते हुए आयुक्त ने पुष्प उत्पादक कृषकों के लिए एफपीओ के गठन और कोल्ड रूम जैसी भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि क्षेत्र में नवाचारों और क्षमता वर्धन को बढ़ावा देने हेतु, आयुक्त ने निर्देश दिए कि किसानों को आधुनिक तकनीक जैसे जल प्रबंधन और टिशू कल्चर लैब में विशेष प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) के लिए जलगांव महाराष्ट्र भेजा जाए। भ्रमण के दौरान कृषकों ने ब्लूबेरी की खेती के लिए सरकारी अनुदान और सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एनवीडीए पाइपलाइन विस्तार की मांग भी रखी, जिस पर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। इस दौरान कलेक्टर राजीव रंजन मीना, संयुक्त संचालक उद्यान दयाराम जाटव, उप संचालक उद्यान नीरज सांवलिया, विभागीय अधिकारी और प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे।

पीएम मित्र पार्क में चल रहे विकास कार्यों का कमिश्नर डॉ. सुदाम खाड़े ने किया निरीक्षण

2,156 एकड़ में विकसित किए जा रहे इस पार्क में अब तक 20,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं

धार। मध्यप्रदेश का महत्वाकांक्षी 'पीएम मित्र पार्क', तेजी से विकसित हो रहा है। इंदौर कमिश्नर डॉ. सुदाम खाड़े ने पीएम मित्र पार्क का दौरा कर वहाँ चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एमपीआईडीसी के अधिकारियों ने डॉ. खाड़े को पार्क की वर्तमान प्रगति, प्रस्तावित निवेश, रोजगार सृजन तथा विभिन्न आधारभूत संरचना विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। डॉ. खाड़े ने पार्क में विकसित की जा रही आवासीय एवं लॉजिस्टिक्स सुविधाओं पर चर्चा की और इनके समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित विकास के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर राजीव रंजन मीना सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। लगभग 2,156 एकड़ में विकसित किए जा रहे इस पार्क में अब तक 20,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनसे 46,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। परियोजना

के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 1,100 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा तीसरे चरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। पार्क में बाह्य विद्युत अधोसंरचना पूर्ण हो चुकी है और इसे विद्युत वितरण लाइसेंस भी मिल चुका है। यहाँ कॉमन फैसिलिटी सेंटर, प्लग एंड प्ले शेड्स जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। यह पार्क राष्ट्रीय राजमार्ग एवं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से चार लेन सड़क द्वारा जुड़ चुका है।

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी- जी राम - जी) के शुभारंभ का जिला स्तरीय आयोजन तिरला में हुआ

धार। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका संवर्धन तथा टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी- जी राम - जी) का प्रदेशव्यापी शुभारंभ 2 जुलाई को किया गया। धार जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम तिरला में किया गया। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर मुख्य

अतिथि के रूप में उपस्थित रही। विधायक धार नीना वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक चौधरी, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण,नागरिक उपस्थित रहे।

भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का सभी जिला स्तरीय कार्यक्रमों में सीधा प्रसारण किया गया, जिससे उपस्थित नागरिक मिशन के उद्देश्यों एवं प्रमुख प्रावधानों से सीधे जुड़े।

इस अवसर पर नागरिकों को मिशन के प्रमुख प्रावधानों, विशेष रूप से 125 दिवस रोजगार गारंटी, डिजिटल कार्यप्रणाली, पारदर्शी भुगतान प्रणाली, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी, सामाजिक अंकेक्षण तथा विकेन्द्रीकृत ग्राम स्तरीय योजना निर्माण की जानकारी प्रदान की गई। राज्य शासन ने सभी जिलों को कार्यक्रम के व्यापक एवं प्रभावी आयोजन के निर्देश दिए हैं।

ई-टोकन व्यवस्था किसानों के लिए बनी परेशानी का कारण

65,648 टोकन लैप्स, सिर्फ 1.27 लाख को मिली खाद

एस. द्विवेदी, बैतूल। ई-टोकन व्यवस्था किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए लागू की गई है, लेकिन यह व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी बन गई है। इसके पीछे कारण ई-टोकन की वैधता की निर्धारित समय अवधि है। यदि किसान समय सीमा में खाद नहीं लेते है तो ई-टोकन लैप्स हो जाते है। जिसके बाद किसानों को दोबारा ई-टोकन जनरेट करना पड़ता है। जिससे किसान परेशान है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 2 लाख 620 ई-टोकन जारी किए गए हैं। इनमें से 1 लाख 27 हजार 564 टोकन पर खाद का वितरण किया गया है, जबकि 65 हजार 648 टोकन लैप्स हो गए। किसानों ने बताया कि पहले ई-टोकन की वैधता केवल 48 घंटे थी। इस अवधि में किसान को टोकन जनरेट कराना, आवंटित केंद्र तक पहुंचना, परिवहन की व्यवस्था करना और लंबी कतार में लगकर खाद लेना पड़ता था। खेतों में बोनी का दबाव, बारिश की अनिश्चितता और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संसाधनों के बीच यह व्यवस्था किसानों के लिए आसान नहीं थी। हजारों टोकन लैप्स होने के बाद अब शासन ने अवधि बढ़ाकर 72 घंटे कर दी है, लेकिन इस अवधि में भी किसान दुकान या सोयायटी नहीं पहुंच पा रहे है। किसानों का कहना है कि जब टोकन में उनके गांव या नजदीकी केंद्र के बजाए

दूसरे विकासखंड की सोसायटी अथवा निजी दुकान का पता दिया जाएगा, तो सीमित समय में वहां पहुंचना संभव नहीं है।

इनका कहना है -

खाद वितरण में ई-टोकन को लेकर किसानों को आ रही समस्याओ को देखते हुए शासन ने ई-टोकन की वैधता को बढ़ाकर तीन दिन कर दिया है। विभाग द्वारा इस सीजन में पिछले साल के लगभग समतुल्य खाद का वितरण किया जा चुका है। हमारा प्रयास है कि जिले में किसानों को खाद की कमी नही होनी पाए।

- रामगोपाल रजक, उप संचालक कृषि विभाग बैतूल

खाद लेने नहीं पहुंचे इसलिए लैप्स हुए टोकन

विभाग का कहना है कि किसान निर्धारित समय में सोसायटी या दुकान तक खाद लेने नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से टोकन लैप्स हो गये। किसानों ने बताया कि सर्वर धीमा होने के कारण कई किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। गांवों में तकनीकी संसाधन सीमित होने से किसान साइबर कैफे का सहारा लेते हैं, जहां एक टोकन के लिए करीब 30 रुपए तक खर्च करना पड़ता है। आंकड़ों में यह दावा सही हो सकता है, लेकिन वितरण की मात्रा बढ़ने भर से व्यवस्था किसान हितैषी नहीं हो जाती। असली कसौटी यह है कि किसान को खाद कब, कहां और कितनी आसानी से मिल रही है। यदि किसान टोकन के लिए पैसे खर्च करे, सर्वर के इंतजार में समय गंवाए और फिर दूसरे ब्लॉक की दुकान तक पहुंचने में अतिरिक्त किराया दे, तो ई-टोकन व्यवस्था उसकी सुविधा नहीं बल्कि एक नई बाधा बन जाती है।

दूसरे ब्लाक की दुकानों का मिल रहा टोकन

सरकार ने ई-टोकन व्यवस्था किसानों की सहुलियत के उद्देश्य से लागू की थी लेकिन यह व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रही है। सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि ई- टोकन में जिस दुकान का पता दिया जा रहा है वह अन्य विकासखंड या दूर की होने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि चांदबेला ग्राम में रहने वाले किसानों को खाद के लिए शाहपुर ब्लाक की खाद दुकानें का पता दिया गया। ऐसे में किसानों का समय और धन दोनों खर्च हो रहे है। किसान गुणवंत ने बताया कि 18 बोरी खाद के लिए उन्हें भीमपुर से शाहपुर आना पड़ा।

65153 एमटी बांटी खाद, 26900 स्टॉक

जिले में खाद के भंडारण के आंकड़े भी उपलब्धता का दावा मजबूत करते हैं। कृषि विभाग के अनुसार जिले को अब तक 92053 मेट्रिक टन खाद मिल चुकी है, जिसमें से विभाग ने 65253 मेट्रिक टन खाद का वितरण कर दिया है, वहीं 26900 मेट्रिक टन खाद का स्टॉक विभाग के पास उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि यूरिया का 56420 एमटी भंडारण किया गया था, जिसमें से 42518 एमटी यूरिया का वितरण किया गया, वहीं 13902 एमटी यूरिया स्टॉक में मौजूद है। इसी तरह एसएसपी 11804 एमटी भंडारण किया था, इसमें से 5239 एमटी खाद का वितरण एवं 6565 एमटी उपलब्ध है। डीएपी का 7987 भंडारण, वितरण 7656 एवं 331 स्टॉक शेष है। एमओपी 2811 एमटी भंडारण किया था। वहीं 1519 एमटी का वितरण और 1292 एमटी स्टॉक उपलब्ध है। एनपीके का 13031 एमटी भंडारण किया था।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संपर्क अभियान 2026 को मिली बड़ी सफलता

2598 शिविरों में 1 लाख 25 हजार से अधिक उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर निराकरण

भोपाल/ग्वालियर। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को उनके घर के नजदीक ही निराकरण करने के उद्देश्य से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित संपर्क अभियान 2026 को सफलता मिली है। 14 मई से शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत भोपाल और ग्वालियर रीजन के 16 जिलों में व्यापक स्तर पर 2598 विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 1 लाख 25 हजार से अधिक उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया।

भोपाल रीजन के वृत्तों में लगे शिविर- भोपाल रीजन के अंतर्गत 191 शिविर शहर वृत्त भोपाल में आयोजित किए गए जिसमें 13046 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया गया, इसके साथ ही बैतुल वृत्त में 230 शिविरों में 13403 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, सीहोर वृत्त में 168 शिविरों में 3908 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, राजगढ़ वृत्त में 189 शिविरों में 2542 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, नर्मदापुरम वृत्त में 175 शिविरों में 16884 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, रायसेन वृत्त में 133 शिविरों में 9907 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, भोपाल (ग्रामीण) वृत्त में 132 शिविरों में 4486 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, विदिशा वृत्त में 102 शिविरों में 6764 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण एवं हरदा वृत्त में 69 शिविरों में 11309 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया गया है।

ग्वालियर रीजन के वृत्तों में लगे शिविर- ग्वालियर रीजन के अंतर्गत मुरैना वृत्त में 201 शिविरों में 6736 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, शहर वृत्त ग्वालियर में 154 शिविरों में 3626 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, भिंड वृत्त में 148 शिविरों में 3334 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, गुना वृत्त में 133 शिविरों में 5428 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, ग्वालियर (ग्रामीण) वृत्त में 131 शिविरों में 2530 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, श्योपुर वृत्त में 98 शिविरों में 3569 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, दतिया वृत्त में 91 शिविरों में 5431 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, शिवपुरी वृत्त में 176 शिविरों में 4582 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण एवं अशोकनगर वृत्त में 77 शिविरों में 7616 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया गया।

इन शिकायतों और सेवाओं पर हुआ त्वरित काम- इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट समाधान करना है। शिविरों में मुख्य रूप से उपभोक्ताओं को त्रुटिपूर्ण बिल, मीटर रीडिंग और अन्य बिलिंग संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया।

नगर पंचायत परिषद ने जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया, लगाएंगी पेवर ब्लाक

नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री धर्मेंद्र शर्मा आदि ने नगर के मुख्य बाजार क्षेत्र में वर्षा से उत्पन्न हो रही जलभराव की समस्याओं वाले स्थानों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के अवसर पर पुरानी नगर पालिका भवन के पीछे बने टीनशेड के दोनों ओर एकत्रित हो रहे पानी का जायजा लिया । इसके साथ बाजार क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का भी निरीक्षण किया। जहाँ जलभराव की

स्थिति निर्मित होती है । नगर पंचायत अध्यक्ष एवं नगरपालिका अधिकारी ने दुकानदारों चर्चा की ।निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष श्रीमती पटेल ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि नगर के किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न होने पाए तथा नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी एवं सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए।। बीकानेर मिष्ठान भंडार के सामने फुटपाथ पर बने गड्ढों एवं जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए पेवर ब्लॉक लगाए जाने के लिए स्थल की नपाई की गई। इस अवसर पर नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंत पटेल,पूर्व पार्षद जगदीश अहिरवार,नगर परिषद के एच.एल. परते, लालबहादुर आम्रवंशी आदि उपस्थित थे।

दीक्षांत समारोह में दुर्गेश को ज्योतिषाचार्य की डिग्री

भोपाल। वरिष्ठ समाज सेवी एवं वाबीसा ब्राह्मण समाज पारमार्थिक ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी श्री देवेन्द्र पाठक जी के सुपुत्र चिरंजीव दुर्गेश को ज्योतिष आचार्य की डिग्री मिलने पर अनंत शुभकामनाएं और अशेष बधाइयां।

ज्योतिष में आचार्य डिग्री प्राप्त महर्षि पाणिनि सँस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सन 2025 के सम्मान व डिग्रीयां प्रदान की गई जिसमें कुलपति ,व मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, स्वामी गोविंददेव गिरी जी ,शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, सहित अनेक विशिष्ठ अतिथियों द्वारा पं.दुर्गेश देवेंद्र पाठक सनावद को ज्योतिष आचार्य (एम ए) करने पर मध्य प्रदेश के दस विशिष्ठ में व इंदौर मैं प्रथम स्थान प्राप्त करने पर विशेष सम्मान कर डिग्री (उपाधि) प्रदान की गयी ।आप गतिमान रहें और समाज का गौरव बढ़ाएं। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रखें।

बायोमेट्रिक उपस्थिति में लापरवाही, कर्मचारी कार्यमुक्त

बैतूल। नगरपालिका में अनुशासन एवं कार्य संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए सीएमओ नवनीत पाण्डेय ने सख्त कदम उठाए हैं। उनके निर्देश पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराने और बिना अनुमति लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले 24 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। नगरपालिका में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में सीएमओ ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले तथा कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। समीक्षा के दौरान ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार कर उन्हें कार्य से पृथक करने का निर्णय लिया गया। सीएमओ नवनीत पाण्डेय ने स्पष्ट कहा कि नगर पालिका में अनुशासनहीनता, अनियमित उपस्थिति और कार्य के प्रति उदासीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने तथा निर्धारित समय पर आ दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। कार्रवाई की जद में आए कर्मचारियों में आउटसोर्स कर्मचारी अंकित यादव, आशीष विश्वकर्मा, दुर्गेश बार्डे, हरीश देवहरे, हिमांशु सेमरे, जतिन रगड़े, मनोज झोबड़े, मोहन वडीवा, नेहल विन्नितकर, निखिल विन्नितकर, पंकज सिंह ठाकुर, पवन दवांदे, राहुल आमझरे, राजेश विश्वकर्मा, रामदयाल उइके, रामरतन सरयाम, रिंकल नागले और शिवशंकर ठाकुर शामिल हैं।

एसपी ऑफिस के पास व्यापारियों से लूट का प्रयास

मिर्च पाउडर झोंककर चाकू दिखाया, शोर मचते ही भागे बदमाश

बैतूल। शहर के गंज थाना क्षेत्र में बुधवार रात दो किराना व्यापारियों से मिर्च पाउडर झोंककर लूट का प्रयास किया गया। व्यापारी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर हमला किया। हालांकि, व्यापारियों के शोर मचाने और लोगों के पहुंचने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना शहर के सबसे संवेदनशील इलाके में हुई, जो पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस लाइन से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, प्रेमी किराना के संचालक ललित कुमार पोपली और निर्मल पोपली बुधवार रात करीब 10 बजे अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। गंज के रामकृष्ण बगिया के पास मुख्य मार्ग से अंदर मुड़ते ही काले और लाल रंग की बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोका। आरोपियों ने व्यापारियों की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया और चाकू दिखाकर लूटने का प्रयास किया। व्यापारियों की चीख-पुकार सुनकर लोग जमा होने लगे। लोगों को अपनी ओर आता देख दोनों बदमाश अपनी बाइक से मौके से फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि बदमाश

पहले से ही व्यापारियों की रेकी कर रहे थे। दुकान बंद होने के बाद उन्होंने व्यापारियों का पीछा किया और वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। गुरुवार दोपहर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन और गंज थाना प्रभारी नीरज पाल पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और जांच-पड़ताल की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाना शुरू कर दिया है। पुलिस निगरानी बदमाशों की गतिविधियों और उनकी मोबाइल लोकेशन भी खंगाल रही है, ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मानव संसाधन हुआ और सुदृढ़

भोपाल। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल द्वारा मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कार्यालय सहायक ग्रेड-तीन के 78 प्रशिक्षुओं की नई भर्ती एवं नियुक्ति की गई है।

नवनियुक्त सभी 78 कार्यालय सहायक ग्रेड-तीन प्रशिक्षुओं ने 29 मई को पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर, भोपाल में कार्यभार ग्रहण कर प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत उन्हें कंपनी के विभिन्न शहर एवं संचालन-संधारण वृत्तों में प्रशिक्षण के शेष मॉड्यूल पूर्ण करने हेतु पदस्थ किया गया है। इससे प्रशिक्षुओं को मैदानी स्तर पर कार्य का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा तथा वे भविष्य में अधिक दक्षता एवं प्रभावशीलता के साथ अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकेंगे।

यह भर्ती कंपनी के मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे प्रदेश के योग्य एवं शिक्षित युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही कंपनी के विभिन्न कार्यालयों एवं क्षेत्रीय इकाइयों में मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाया गया है। कार्यालय सहायक ग्रेड-तीन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति से कंपनी की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक गति मिलेगी तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएँ उपलब्ध कराने में सहायता प्राप्त होगी।

मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी हो, किसानों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ : प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेन्द्र चौहान

हीरालाल गोलानी सोहागपुर। नवीन बस स्टैंड परिसर में समस्त कांग्रेस परिवार के तत्वावधान में किसानों की समस्याओं एवं अधिकारों को लेकर विशाल धरना-प्रदर्शन प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेन्द्र चौहान, सोहागपुर विधानसभा चुनाव प्रत्याशी रहे पुष्पराज सिंह पटेल,प्रदेश महामंत्री केलू उपाध्याय, मेहरबानसिंह , पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय,छोटू हजूर खर्चा, कांग्रेस नेता हरगोविंद पूर्बिया, शैलेन्द्र दीवान , सुरेखा शाह प्रमुख रूप से उपस्थित थे। नवीन बस स्टैंड पर हजारों की संख्या में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान, अधिकार और उनके हितों की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ती है,लड़ती रहेगी। आपने कहा कि यदि सरकार किसानों की इन न्यायोचित मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है। तो कांग्रेस किसानों के लिए व्यापक जन आंदोलन करने को बाध्य

होगी। सोहागपुर विधानसभा चुनाव प्रत्याशी रहे पुष्पराज सिंह पटेल ने अपने पारम्परिक जोशीले अंदाज में उद्बोधन देते हुए प्रदेश भाजपा सरकार कई कटाक्ष करते सरकार को किसान विरोधी करार दिया। आपने आगे कहा कि प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण अन्नदाता लगातार परेशान हो रहा है। उन्होंने किसानों की ओर से सरकार के समक्ष चार प्रमुख मांगें रखीं। जिसमें मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी तत्काल सुनिश्चित की जाए, खाद वितरण में लागू टोकन सिस्टम को पूरी तरह बंद किया जाए, ताकि किसानों को अनावश्यक परेशानी और घंटों इंतजार का सामना न करना पड़े, सोहागपुर में स्थायी मूंग तुलाई केंद्र स्थापित किया जाए, जिससे क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज की तुलाई के लिए दूसरे स्थानों पर न जाना पड़े।

गेहूं एवं चने की खरीदी का पिछले तीन महीनों से लंबित भुगतान किसानों को तत्काल किया जाए। कार्यक्रम को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। सभा के उपरांत भीगते बरसाती पानी में नवीन बस स्टैंड से हजारों किसानों एवं कांग्रेस जनों ने रैली निकाली। इस रैली जमकर नारेबाजी की गई।

अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर बबीता राठौर को मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर ठाकुर,नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल, जिला जनपद पंचायत सदस्य दौलतराम पटेल, राजकुमार रघुवंशी, वकील मंगलसिंह रघुवंशी, वकील बी के शर्मा,राजा भैया पटेल, कोमलसिंह, जालमसिंह गणेश अहिरवार जेपी पटेल , अजय ठाकुर रिषभ दीक्षित भूरा पटेल हरिशंकर पटेल सहित भारी संख्या में किसान उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

रेत के अवैध उत्खनन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, दो पनडुब्बी मशीनें जब्त

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार, 29 जून 2026 को तहसील सिवनी मालवा के ग्राम बाबरी एवं पथाडा क्षेत्र में संयुक्त टीम द्वारा रेत के अवैध उत्खनन की जांच की गई। जांच के दौरान दो पनडुब्बी मशीनें अवैध रूप से रेत उत्खनन करते हुए पाई गईं, जिन्हें मौके से जब्त कर पुलिस थाना सिवनी मालवा में अभिरक्षा में रखा गया है। संयुक्त कार्रवाई में नायब तहसीलदार श्रीमती पूनम सिंह सलामे, खनि निरीक्षक सुश्री पिंकी चौहान तथा पुलिस बल की उपस्थिति रही। टीम द्वारा अवैध उत्खनन में प्रयुक्त मशीनों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध निरंतर अभियान जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सीहोर सहित सभी जनपदों में आयोजित हुए जल गंगा संवर्धन अभियान समापन कार्यक्रम

सीहोर (निप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर सीहोर जनपद के ग्राम पाटन सहित सभी जनपदों में जनपद स्तरीय समापन कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने सहभागिता की और जल संरक्षण का संकल्प लिया। ग्राम पाटन में आयोजित जनपद स्तरीय कार्यक्रम में सीहोर विधायक श्री सुदेश राय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश सरकार ने जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने सभी नागरिकों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने तथा वर्षा जल के अधिकतम संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में जनपद सीईओ श्रीमती नमिता बघेल सहित सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक सहित ग्रामवासी उपस्थित थे। इसी प्रकार भैरूंदा के ग्राम गिल्लौर में भी जनपद स्तरीय समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम भैरूंदा जनपद सीईओ श्री संजय अग्रवाल ने सभी को जल संरक्षण की शपथ दिलाई और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। आष्टा के ग्राम गोविंदपुरा में भी जनपद स्तरीय समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम जनपद सीईओ श्री अमित व्यास और एई शुभम रंगडाले ने सभी जल संरक्षण की शपथ दिलाई और जल संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया।

कलेक्टर के निर्देश पर चौतलाय में तालाब की 1.63 हेक्टेयर शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम चौतलाय में शासकीय तालाब भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान ग्राम चौतलाय स्थित खसरा क्रमांक 151, कुल रकबा 1.631 हेक्टेयर शासकीय तालाब भूमि पर किए गए कच्चे अतिक्रमण को हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण हटाने के उपरांत तालाब की भूमि को विधिवत ग्राम पंचायत चौतलाय को सुपुर्द किया गया, जिसे ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा ग्रहण किया गया। संपूर्ण कार्रवाई शांतिपूर्ण एवं विधिसम्मत ढंग से संपादित की गई। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा द्वारा ग्राम पंचायत में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान तालाबों एवं अन्य शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर के निर्देशों के परिपालन में राजस्व विभाग द्वारा निरंतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के प्रथम चरण में संबंधित अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए सूचित किया गया था। इसके पश्चात राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमि का चिन्हांकन कराया गया। चिन्हांकन उपरांत लगभग 1.63 हेक्टेयर शासकीय तालाब भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई में नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी श्री पूनमसिंह सलामे, संबंधित राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारीगण तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम उपस्थित रही।

जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन: मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने जल संरक्षण और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधरोपण

10 हजार स्मार्ट क्लास शुरू करने की तैयारी

विदिशा (निप्र)। मध्यप्रदेश शासन के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने मंगलवार को विदिशा के अटल पार्क में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह में सहभागिता की। जिले में 19 मार्च से 30 जून तक संचालित इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण, जल स्त्रोतों के पुनर्जीवन और जनसहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में व्यापक कार्य किए गए।

कार्यक्रम में मंत्री श्री सिंह ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान का सफल संचालन हुआ है। इस जनअभियान में जनप्रतिनिधियों , प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता रही, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से प्राचीन जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार, नए तालाबों का निर्माण तथा जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। मध्यप्रदेश ने जल संरक्षण के क्षेत्र में पूरे देश में उत्कृष्ट कार्य कर एक नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि हम सभी ने मिलकर अपनी प्राचीन जल धरोहरों को संवारने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के साथ-साथ 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत भी प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया गया। वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार है। उन्होंने कहा कि 'जल गंगा संवर्धन अभियान का यह समापन नहीं, बल्कि एक विराम है।

अगले वर्ष यह अभियान और अधिक व्यापक रूप में पुनः प्रारंभ होगा तथा जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य निरंतर जारी रहेगा।'

उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित एवं समृद्ध राष्ट्र बनाने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देश का नेतृत्व युवा पीढ़ी करेगी, इसलिए ऐसे जनहितकारी अभियानों में उनकी सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने इस जनअभियान के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार एवं अभिनंदन भी व्यक्त किया।

शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियां : स्कूल शिक्षा विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल है। एक जुलाई से नए शैक्षणिक सत्र के साथ सभी विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें, साइकिल, यूनिफॉर्म सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सांदीपनि विद्यालय, मॉडल स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल तथा नवोदय विद्यालयों में निजी विद्यालयों की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 10 हजार स्मार्ट क्लास प्रारंभ करने की तैयारी भी की जा रही है।

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत किया पौधरोपण -

कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत अटल पार्क में आम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन का संदेश दिया। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रकृति के प्रति दायित्व है। पौधरोपण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण का संकल्प लिया।

अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुरस्कृत

मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने विदिशा जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदाय कर सम्मानित किया है।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के अलावा कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी, जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोडिया एसडीएम श्री क्षितिज शर्मा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

ग्राम सतपिपलिया में जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन कार्यक्रम आयोजित

सीहोर (निप्र)। जल एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन तथा जन-जागरूकता के लिए प्रदेशभर के साथ ही सीहोर जिले में 19 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया गया। अभियान के समापन अवसर पर जिले के ग्राम सतपिपलिया में जिला स्तरीय समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री करणसिंह वर्मा शामिल हुए। उन्होंने गांव के तालाब में श्रमदान किया, पौधारोपण किया और जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री करणसिंह वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे जनआंदोलन का स्वरूप दे रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान केवल शासकीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। उन्होंने कहा कि जल का प्रत्येक स्त्रोत हमारी अमूल्य धरोहर है, इसलिए उसके संरक्षण और संवर्धन में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने अभियान को सफल बनाने वाले जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों तथा नागरिकों की सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही जल संकट का स्थायी समाधान संभव है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि अभियान की भावना को केवल 30 जून तक सीमित न रखें, बल्कि वर्षभर जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पौधरोपण तथा जल स्त्रोतों के संरक्षण के कार्यों को निरंतर जारी रखें। उन्होंने कहा कि जल बचाना ही भविष्य को सुरक्षित बनाना है और इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजस्व मंत्री ने नागरिकों की समस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि अभियान के दौरान जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से जिले में व्यापक स्तर पर जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य किए गए।

जिले में 'ज्ञान भारतम् मिशन' अंतर्गत चलाया जा रहा पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान

रायसेन (निप्र)। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित 'ज्ञान भारतम् मिशन' के अंतर्गत कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशन में रायसेन जिले में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की पांडुलिपियों का सर्वे, सूचीकरण एवं डिजिटलीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

अभियान के दौरान बरेली एसडीएम श्री अंकित जैन को प्राचीन पांडुलिपि प्राप्त हुई हैं जिसमें गौरगजगढ़ (गौरझामगढ़) राजमंडल का इतिहास है। पांडुलिपि के प्रारंभिक भाग में उल्लेख है कि यह गौरगजगढ़ (गौरझामगढ़) राजमंडल का इतिहास है। इसमें लिखा है कि गोंड राजवंश की स्थापना हुई और विभिन्न राजाओं ने शासन किया। प्रारंभिक शासकों में राजा भीमनाग, भीमकोट, गोरखनाथ से जुड़े उल्लेख, राजा गोरक्ष शाह आदि का वर्णन मिलता है। आगे राजा अमर सिंह का उल्लेख है, जिन्होंने लगभग 28 वर्ष शासन किया। उनके बाद विक्रम सिंह, फिर भीम

देव और अन्य शासकों का वर्णन आता है। पांडुलिपि के मध्य भाग में राजा गोपाल शाह का उल्लेख है जिन्होंने एक नया नगर बसाया। इस नगर के आसपास जैसे बारी गढ़, चौकी गढ़, पंचमेढ़ी, छनेरा आदि का भी उल्लेख मिलता है।

पंचमेढ़ी का अर्थ है पांच देवताओं का स्थान (ये गोंडी भाषा का शब्द है।गोंडो की भाषा में तेलुगु, गोंडी, हिंदी, संस्कृत के शब्द मिले जुले होते हैं) बाद में रामचंद्र, जगत सिंह, महाराज सिंह, दुर्जनमल, प्रतापादित्य, यशराज आदि राजाओं का क्रम आता है। कुछ राजाओं द्वारा किले, नगर और तालाब बनवाने तथा राज्य विस्तार का वर्णन है। पांडुलिपि के अंतिम भाग में उल्लेख है कि इसमें त्रिलोकचंद्र, त्रिभुवन राय, पृथ्वीसिंह, भारतीचंद्र, मदन सिंह, रामशाह, उदयवर्धन सिंह आदि शासकों का उल्लेख मिलता है। परमार राजाओं से युद्ध और संधियों का वर्णन है। एक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का उल्लेख भी है।

आगामी मानसून के दौरान रहवासी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो सभी सीएमओ यह सुनिश्चित करें : कलेक्टर

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। समय सीमा की बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री हिमांशु जैन, अपर कलेक्टर श्री राजेश शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, डिप्टी कलेक्टर डॉ बबीता राठौर, श्रीमती नीता कोरी सहित अन्य संबंधित अधिकारीकरण उपस्थित रहे।

बैठक में मूंग उपार्जन, सीएम हेल्पलाइन, वर्षाकालीन तैयारियों, नवांकुर अभियान, जनकल्याण शिविर, निर्माण कार्यों तथा वन अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर मूंग उपार्जन के लिए तैयार किए जाने हेतु उपार्जन केंद्रों

का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों का सत्यापन आगामी दो दिवसों में शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए। सभी एसडीएम किसान संगठनों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करें तथा उपार्जन की समस्त तैयारियां समय पर सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक अनुभाग के सभी उपार्जन केंद्रों पर अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने सभी अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की प्रतिदिन की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। विभागवार समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले एवं निम्न ग्रेडिंग वाले विभागों को एक सप्ताह के भीतर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण के माध्यम से अपनी स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए। आगामी वर्षाकाल को देखते हुए कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में कहीं भी जलभराव अथवा वाटर चोकिंग जैसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को नालों की सफाई व्यवस्था का नियमित निरीक्षण एवं समीक्षा कर रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में वर्षाकाल के दौरान जिले में हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित नवांकुर अभियान की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सीड बॉल निर्माण एवं उनके चयनित स्थानों पर व्यापक वितरण के लिए सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा के दौरान बीजों को पर्याप्त नमी एवं पोषण मिल सके और अधिकाधिक पौधे विकसित हो सकें। कलेक्टर ने गत सप्ताह आयोजित जनकल्याण शिविरों में खराब प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन विभागों के निर्माण कार्य भूमि आवंटन अथवा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण लंबित हैं, उन्हें संबंधित एसडीएम से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने गंजबासौदा की होनहार बेटी का बीपीएससी में चयन होने पर किया सम्मानित

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज विदिशा के गंजबासौदा विकासखंड के ग्राम सींगाखेड़ी की प्रतिभाशाली बेटी सुश्री रानू रघुवंशी का बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा में चयन होने पर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दी हैं।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने रानू रघुवंशी की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की बेटियाँ भी अपनी मेहनत और लगन से बड़ी सफलताएँ प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने चयनित बालिका की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वह अपने गाँव एवं आसपास की बालिकाओं का उत्साहवर्धन करें और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित करें तथा अपने अनुभव साझा कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें।

सुश्री रानू रघुवंशी की इस उपलब्धि से ग्राम सींगाखेड़ी सहित पूरे जिले में हर्ष का वातावरण है। उनकी सफलता अन्य युवाओं , विशेषकर बालिकाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

जनसहभागिता से ही संभव होगी जल सुरक्षा : प्रभारी मंत्री श्री पटेल

बैतूल (निप्र)। प्रदेशव्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर मंगलवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत खेड़ी सांवलीगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री एवं सांसद श्री दुर्गादास उईके, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार, उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे, सरपंच श्रीमती शर्मिला ठाकुर, श्रीमती सरोज राठौर, श्रीमती अनीता डांगे, श्री पिंटू परिहार, श्री कांतिलाल यादव, श्री नितिन बरसाकर, श्री कमल मालवीय तथा अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, एसडीएम डॉ अभिजीत सिंह, अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत श्रीमती इंदिरा महतो सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम से पूर्व प्रभारी मंत्री श्री पटेल और केंद्रीय मंत्री श्री उईके द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान के सफल संचालन के लिए जिलेवासियों को बधाई दी तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश पढ़कर सुनाया। मुख्यमंत्री के संदेश में बताया गया कि जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 के अंतर्गत प्रदेशभर में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लगभग 3.62 लाख कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है। लगभग 10 हजार 514 करोड़ रुपए की लागत से खेत तालाब, कूप रिचार्ज, अमृत सरोवर, चेकडेम, जलाशयों के जीर्णोद्धार, नालों की सफाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल गुणवत्ता परीक्षण, नदी संरक्षण तथा जनजागरूकता से जुड़े व्यापक कार्य किए गए हैं।

प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जल संरक्षण और वृक्ष संरक्षण एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां जल होगा, वहां हरियाली होगी और जहां हरियाली

होगी, वहां जल का संरक्षण होगा। उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत प्रत्येक परिवार से कम से कम एक पौधा लगाने और उसका संरक्षण सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय को जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया।

केंद्रीय राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उईके ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान का पूरे प्रदेश में सफल क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने का अभियान है। वृक्ष ही जल को अवशोषित और संरक्षित रखने का कार्य करते हैं, इसलिए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण किया जाना आवश्यक है। उन्होंने घर का पानी घर में तथा खेत का पानी खेत में रोकने की दिशा में जनसहभागिता बढ़ाने का आह्वान किया और अभियान के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार ने कहा कि बैतूल जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जो प्रदेश के लिए मॉडल के रूप में स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में जल सबसे बड़ी आवश्यकता होगी, इसलिए प्रत्येक घर में जल संरक्षण एवं रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर बताया गया कि 19 मार्च से 30 जून 2026 तक संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान जिले में कुल 45 हजार 833 जल संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संवर्धन कार्य पूर्ण किए गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 7 हजार 397, वन विभाग द्वारा 20 हजार 565, नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 8 हजार 717, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 4 हजार 69, जन अभियान परिषद द्वारा 3 हजार 482, उद्यानिकी विभाग द्वारा 669, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 390 तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 352 कार्य पूर्ण किए गए। अन्य विभागों द्वारा भी 192 कार्य पूर्ण कर अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। कार्यक्रम में जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। जनभागीदारी के माध्यम से 1500 से अधिक जल संरचनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अध्यक्ष ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति, जन अभियान परिषद, कान्हावाड़ी, विकासखंड घोड़ाडोंगरी के श्री नरेंद्र ऊईके को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत खेड़ला के सचिव श्री अशोक वामनकर, ग्राम पंचायत कुम्हली के रोजगार सहायक श्री संदीप बारस्कर, ग्राम पंचायत नीमझिरी के सरपंच श्री रामदीन पिपरदे, एनआरएलएम बैतूल की श्रीमती मीरा सरते तथा 'एक बगिया मां के नाम' पहल से जुड़ी श्रीमती ललिता भागवले को भी सम्मानित किया गया।

महिला के बाल काटे, कपड़े फाड़कर गांव में घुमाया

उज्जैन में ससुरालवालों ने पति समेत पीटा, 11 पर केस दर्ज, 3 गिरफ्तार

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन जिले में एक महिला को अर्धनग्न कर गांवभर में घुमाने का मामला सामने आया है। आरोप उसके ससुरालवालों पर है। घटना अरनिया वेणा गांव में 30 जून की है। झारड़ा थाना पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी 8 की तलाश की जा रही है।

टीआई आनंद भाबोर ने बताया कि पीड़िता की शादी अरनिया वेणा गांव में हुई थी। बाद में गांव के ही एक युवक से उसका प्रेम संबंध हो गया। 2023 में वह अपने पहले पति को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई। दोनों ने शादी कर ली और इंदौर जाकर रहने लगे।

कुछ समय बाद महिला ने नए ससुराल की जमीन में हिस्सेदारी की मांग की। इसी सिलसिले में वह 30 जून को अरनिया वेणा स्थित ससुराल पहुंची। यहां उसका ससुरालवालों से विवाद हो गया।

दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस गए

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 9 बजे वह अपने कमरे में थी, तभी सुमेर सिंह, कचरू सिंह और बद्रीलाल अन्य लोगों के साथ दरवाजा तोड़कर घुस आए। उन्होंने बाल और हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर निकाला, जहां ससुराल की तीन महिलाओं समेत दूसरे सदस्य मौजूद थे। आरोपियों ने पीड़िता के सिर के बाल काट दिए। कपड़े फाड़कर उसे अर्धनग्न कर दिया। फिर गले में जूते-चप्पलों की माला पहनाकर गांव में जुलूस निकाला।

आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उसके और पति के साथ मारपीट की गई। जान से मारने की धमकी दी गई। महिला की आंख, गाल, सिर, पेट जबकि पति के चेहरे, सीने और पेट पर चोटें आई हैं। टीआई आनंद भाबोर ने कहा-सुमेर, कचरू और बद्रीलाल को जेल भेज दिया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

शिवपुरी में ट्रक पुलिया से टकराया, हेल्पर की मौत

ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, केबिन में फंस गए थे दोनों

शिवपुरी (नप्र)। शिवपुरी जिले के सतनबाड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात सड़क हादसा हो गया। एनएच-46 पर पाठक होटल के पास तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गया। हादसे में ट्रक के हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार, ट्रक शिवपुरी से ग्वालियर जा रहा था। रात करीब 1 बजे सतनबाड़ा थाना क्षेत्र में एनएच-46 स्थित पाठक होटल के पास यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

केबिन में फंस गए थे दोनों

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे चालक और हेल्पर को बाहर निकाला गया। दोनों को तुरंत शिवपुरी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने 38 वर्षीय हेल्पर मंगल सिंह राजपूत, निवासी भानपुर जिला मंदसौर, को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल चालक का इलाज जारी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल दुर्घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।

29 दिन से अंधेरे में सीएम संजीवनी पॉली क्लीनिक

बिजली बिल बकाया होने का आरोप, दोपहर 12:30 बजे तक डॉक्टर-स्टाफ भी नहीं पहुंचे

भोपाल (नप्र)। भोपाल के खानूगांव स्थित मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लीनिक में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल नजर आ रही हैं। यहां पिछले 29 दिनों से बिजली आपूर्ति बंद होने का दावा स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने किया है। बिजली नहीं होने से क्लीनिक का संचालन प्रभावित हुआ है, वहीं बीपी जांच जैसी सामान्य सुविधाएं भी नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे तक क्लीनिक में डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी मौजूद नहीं था, जिससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को निराश होकर इंतजार करना पड़ा।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस पॉली क्लीनिक में प्रतिदिन करीब 40 से 50 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। बिजली नहीं होने और डॉक्टरों की अनियमित मौजूदगी के कारण मरीजों को

पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि महीने भर में यहां एक हजार से अधिक मरीज पहुंचते हैं। इस बारे में सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा से कई बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, मगर उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

3 जून से बिजली नहीं- मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मोहम्मद जहीर ने बताया कि क्लीनिक में 3 जून से बिजली नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने पर बताया गया कि बिजली बिल जमा नहीं होने के कारण कनेक्शन काटा गया है।

वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लगातार यही जवाब मिला कि आज बिल जमा हो जाएगा, लेकिन 15 दिन से अधिक समय गुजरने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। उनका आरोप है कि अब संबंधित अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। जहीर का कहना है कि बिजली नहीं होने से सबसे ज्यादा असर पैथोलॉजी जांच पर पड़ा है। महिला मरीजों के लिए आने वाली स्त्री रोग विशेषज्ञ भी गर्मी और बिजली की समस्या के कारण अधिक देर तक नहीं बैठ पातीं। हार्ट और बीपी के मरीजों की जांच भी प्रभावित हो रही है।

मरीजों ने कहा

मरीज जाहिदा बेगम ने बताया कि वह पिछले करीब 20 दिनों से बीपी चेक कराने आ रही हैं, लेकिन एक बार भी जांच नहीं हो सकी। उनका कहना है कि बिजली नहीं होने से मशीन चार्ज नहीं हो पाती, इसलिए बिना बीपी जांच कराए ही दवा लेकर लौटना पड़ता है। उन्होंने बताया कि चक्कर आने जैसी परेशानी होने के बावजूद उनकी जांच नहीं हो पा रही। समाजसेवी फहीमुद्दीन चौधरी ने आरोप लगाया कि बिजली की समस्या तो लगभग एक महीने से है, लेकिन डॉक्टरों का समय पर नहीं आना पुरानी समस्या है। उनके अनुसार, कई बार डॉक्टर 11 या 12 बजे पहुंचते हैं और थोड़ी देर बाद वापस चले जाते हैं। इस दौरान मरीज गर्मी में घंटों इंतजार करते रहते हैं और कई बार बिना इलाज कराए लौट जाते हैं।

महिला बोली- मजबूरी न होती तो नरक में नहीं रहते

खिड़की के सामने कचरा, जर्जर दीवारें, भोपाल में 15 साल में बिल्डिंगें बनी खंडहर

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल के नेहरू नगर के शबरी नगर मल्टी में लोगों की सुबह कचरे की बदबू से होती है और रात इस डर में बीतती है कि कहीं बिजली की कोई तेज कड़क मल्टी की दीवारों को न गिरा दे।

मल्टी में रहने वाली संगीता कहती है मजबूरी न होती तो इस नरक में नहीं रहते। बारिश में हाल और बुरे हो जाते हैं। नालियां जाम हो जाती हैं घरों में सीवेज का पानी आता है। मकान गिरने का डर हमेशा बना हुआ है।

दूसरी महिला ने कहा कि नगर निगम कचरे का पैसा पानी का पैसा सब लेने आते हैं पर सफाई करने कोई नहीं आता है। हमारे जनप्रतिनिधि भी यहां तभी आते हैं जब चुनाव का समय होता है। इससे अच्छा तो हमारी झुग्गियां थीं।

अनिता कहती है कि हम दुआ करती हूं कि बारिश न हो। बारिश में मेरा दो कमरों का फ्लैट झरना बन जाता है। बेडरूम किचन हर जगह पानी रिसता है। 15 साल हो गए पर कोई सुधार नहीं

कराया गया। मल्टी की छतों पर इतनी घास है जितनी कि खेतों पर नहीं होगी।

इस शबरी नगर में 40 से ज्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। जिसमें से कुछ 20 और कुछ 15 साल पुरानी हैं। इन बिल्डिंग्स में एक हजार से ज्यादा से परिवार रहते हैं।

भोपाल की ज्यादातर मल्टियों का यही हाल- ये केवल एक मल्टी नहीं है, भोपाल की ज्यादातर मल्टियों का यही हाल है। चाहे वो अर्जुन नगर, श्याम नगर और राहुल नगर हों या बीडीए का बनवाया अंजली कॉम्प्लेक्स हो। मकान जर्जर हैं, नालियां खुली हैं और उनमें कचरा जमा है।

लोगों का कहना है कि नगर निगम हमसे टैक्स लेती है और मेंटेनेंस हमें खुद कराने के लिए कहती है। यहां 20 से 30 बिल्डिंगों में 110 घर हैं। सभी डर के साये में जी रहे हैं कि कहीं कोई हादसा न हो जाए।

महापौर ने कहा- नगर निगम काम कर रही है- महापौर मालती राय ने कहा कि चाहे जेएनयूआरएम, एएचपी, हाउसिंग बोर्ड, बीडीए या अन्य योजनाओं के तहत बनी इमारतें हों, यदि वे जर्जर स्थिति में हैं तो उन्हें चिन्हित करना और उनमें रहने वाले लोगों को तत्काल भवन खाली करने की सूचना देना नगर निगम की जिम्मेदारी है। नगर निगम ने ऐसी इमारतों की पहचान शुरू कर दी है।

इसके साथ ही गंदगी, सीवेज और जल निकासी की समस्याओं वाले क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया गया है। जिन स्थानों पर आउटलेट बंद होने से जलभराव हो रहा है, वहां उन्हें खुलवाया जा रहा है।

28 साल पुराने केस में उम्रकैद के दोषी को नहीं ढूंढ पाई भोपाल पुलिस

हाईकोर्ट ने 15 दिन का दिया अल्टीमेटम, जीपीएस लोकेशन मांगी

जबलपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली और इन्वेस्टिगेशन के तौर-तरीकों पर जबलपुर हाईकोर्ट ने बेहद तीखी और अभूतपूर्व टिप्पणी की है। मर्डर केस के एक उम्रकैद के दोषी को सालों बाद भी गिरफ्तार न कर पाने पर अदालत ने भोपाल पुलिस की खिंचाई की है। अब पुलिस को कोर्ट में सिर्फ कागजी रिपोर्ट नहीं, बल्कि आरोपी को ढूंढने जाने वाली टीमों की जीपीएस लोकेशन और वीडियो सबूत भी सौंपने होंगे।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए के सिंह की खंडपीठ ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत पेशी से अस्थायी राहत देते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 15 दिनों का अंतिम समय दिया है। दरअसल, यह पूरा मामला भोपाल के जहांगीराबाद इलाके के रहने वाले नवाब सेंटिंगवाला से जुड़ा है, जिसे एक हत्या के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आरोपी ने 1996 में हाईकोर्ट में अपील दायर की, जहां से उसे जमानत मिल गई। जमानत पर बाहर आते ही वह अदालती सुनवाइयों से गायब हो गया, जिसके बाद उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ। इस मामले में जहांगीराबाद एसीपी बिट्टू शर्मा भाटेले द्वारा पेश की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट को कोर्ट ने अधूरे मन से तैयार की गई माना और पुलिस कमिश्नर को तलब कर लिया था।

जबलपुर में तीन तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला

पति ने किया दूसरा निकाह, पत्नी पहुंची पुलिस के पास, बोली-पूरा परिवार शामिल है

जबलपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश के जबलपुर में तीन तलाक का एक मामला सामने आया है। गढ़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर तीन तलाक देने, घर से निकालने और दूसरी महिला के साथ रहने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता तस्लीम ने पुलिस को बताया कि करीब तीन वर्ष पहले बड़े मदार छल्ला निवासी मोहम्मद शहनवाज से उसका निकाह हुआ था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद पति का व्यवहार बदल गया। वह देर रात घर आने लगा और पूछने पर उसके साथ मारपीट करता था।

एक सप्ताह से चल रहा था विवाद

महिला का आरोप है कि कुछ महीने पहले उसे पता चला कि उसके पति के किसी अन्य महिला से प्रेम संबंध हैं। पहले वह कभी-कभार उस महिला के घर जाता था, लेकिन बाद में अक्सर वहीं रहने लगा और कई बार रात भी वहीं बिताने लगा। तस्लीम के अनुसार पिछले एक सप्ताह से दोनों के बीच लगातार विवाद हो रहा था। पति बार-बार उसे मायके चले जाने के लिए कहता था। विरोध करने पर मारपीट करता था और घर खर्च के लिए पैसे देना भी बंद कर दिया था। महिला का यह भी आरोप है कि पति बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहा था।

एमपी में 2548 आंगनबाड़ी पदों पर होगी भर्ती

12वीं पास स्थानीय महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता

भोपाल (नप्र)। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर पोषण प्रबंधन को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 2,548 पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जा रही हैं।

स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता- भर्ती में स्थानीय पात्रताधारियों को प्राथमिकता मिलेगी। कुल रिक्तियों में से 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और 1,767 पद आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन पदों पर चयन के लिए पारदर्शिता और स्थानीय प्रतिनिधित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। नियमों के मुताबिक, आवेदिका का उसी राजस्व ग्राम या शहरी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है, जहां का पद रिक्त है। किसी अन्य ग्राम या वार्ड की महिला इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी।

न्यूनतम योग्यता हायर सेकण्डरी, आयु सीमा 18-35 वर्ष तय

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा के मापदंडों के अनुसार, दोनों ही पदों के लिए आवेदिकाओं का हायर सेकेंडरी अर्थात् 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों या अशासकीय बोर्डों की अंकसूचियों को तभी मान्यता दी जाएगी जब वे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश की समकक्षता सूची में शामिल हों। साथ ही 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आवेदिका की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना आवश्यक है, जिसकी पुष्टि के लिए 10वीं बोर्ड की अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन के दौरान सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करने होंगे, जिसके लिए निर्धारित शुल्क 100 रुपये और 18 प्रतिशत जीएसटी तय किया गया है।

इससे स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता मिलने से मैदानी स्तर पर सेवाओं का कुशल संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।

ऑनलाइन आवेदन केवल 13 जुलाई तक स्वीकार होंगे: भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रहेगी। इसमें एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इच्छुक महिला अभ्यर्थी चयन पोर्टल पर जाकर 1 जुलाई 2026 से अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा कर सकती हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है, जबकि भरे गए फॉर्म में किसी भी प्रकार के त्रुटि सुधार के लिए 15 जुलाई 2026 तक का समय दिया जाएगा। विभाग द्वारा स्पष्ट किया है कि केवल पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। किसी भी स्तर के कार्यालय में ऑफलाइन भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

रिक्त पदों की जिलेवार स्थिति: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों के अनुसार जिलेवार स्थिति इस प्रकार है। आलीराजपुर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 10 तथा आंगनवाड़ी सहायिका के 22 पद रिक्त हैं। इंदौर जिले में कार्यकर्ता के 20 एवं सहायिका के 43 पद रिक्त हैं। खंडवा जिले में कार्यकर्ता के 15 तथा सहायिका के 32 पद रिक्त हैं। खरगोन जिले में कार्यकर्ता के 34 एवं सहायिका के 40 पद रिक्त हैं। झाबुआ जिले में कार्यकर्ता के 21 तथा सहायिका के 23 पद रिक्त हैं। धार जिले में कार्यकर्ता के 30 एवं सहायिका के 82 पद रिक्त हैं। बड़वानी जिले में कार्यकर्ता के 14 तथा सहायिका के 44 पद रिक्त हैं। बुरहानपुर जिले में कार्यकर्ता के 7 एवं सहायिका के 25 पद रिक्त हैं।

आगर मालवा जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 6 तथा सहायिका के 25 पद रिक्त हैं। उज्जैन जिले में कार्यकर्ता के 31 एवं सहायिका के 45 पद रिक्त हैं। देवास जिले में कार्यकर्ता के 16 तथा सहायिका के 35 पद रिक्त हैं। नीमच जिले में कार्यकर्ता के 8 एवं सहायिका के 32 पद रिक्त हैं। मंदसौर जिले में कार्यकर्ता के 9 तथा सहायिका के 25 पद रिक्त हैं। रतलाम जिले में कार्यकर्ता के 31 एवं सहायिका के 62 पद रिक्त हैं। शाजापुर जिले में कार्यकर्ता के 8 तथा सहायिका के 22 पद रिक्त हैं।